राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 301 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, गुरूवार ,06 मई 2021, मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

यूपी में सोमवार तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

लखनऊ, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण बने गंभीर हालात को देखते हुए योगी सरकार ने लॉकडाउन सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया है। अभी तक गुरुवार सुबह सात बजे तक ही बंद की घोषणा की गई थी पर स्थिति को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ये आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 के साथ हुई बैठक में दिए। बता दें कि 29 अप्रैल को योगी सरकार ने प्रदेश में शुक्रवार शाम आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया था और फिर तीन मई को दो दिनों के लिए इसे और बढ़ा कर गुरुवार (6 मई) सुबह सात बजे तक कर दिया।

दीपिका पादुकोण कोरोना संक्रमित

मुंबई, (एजेंसी)। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई हैं। हालांकि ये खबर दीपिका या उनकी टीम की तरफ से कन्फर्म नहीं की गई है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले दिनों वे अपने परिवार से मिलने बेंगलुरु गईं थीं। तभी वे संक्रमित हो गईं। इसके पहले मंगलवार दोपहर को उनके पिता और पूर्व नेशनल बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण के संक्रमित होने और बेंगलुरु के हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर सामने आई थी। प्रकाश के अलावा उनकी पत्नी उज्जला और बेटी अनिशा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं।

स्वास्थ्य संसाधनों के लिए आरबीआई ने खोला खजाना

नई दिल्ली। कोविड की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के बीच आरबीआई ने अपना खजाना खोल दिया है। इस बार आरबीआई ने अपने खजाने का मुंह हेल्थ सेक्टर और स्मॉल फाइनेंस की ओर किया है। जहां हेल्थ सेक्टर को 50 हजार करोड़ रुपए के बूस्टर डोज का ऐलान किया गया है। वहीं दूसरी ओर स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का टीएलआरटीओ लाने का भी ऐलान हुआ है। इस मौके पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना कर सेकंड वेव ने इकोनॉमी पर गहरा असर डाला है। वैसे ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत देखने को मिल रहे हें।

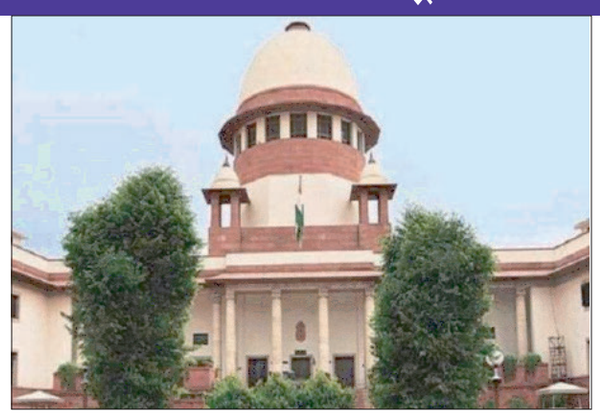

दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- राजधानी को हर हाल में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे केंद्र

नई दिल्ली। दिल्ली समेत तमाम राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा, आज आधी रात तक हुई सप्लाई की हम कल सुबह 10.30 बजे जानकारी लेंगे। सरकार हमें सप्लाई सुनिश्चित करने की योजना और व्यवस्था पर भी जानकारी दे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कोविड वैश्विक महामारी बहुत गंभीर चरण में है और इसके साथ ही उसने केंद्र से पिछले तीन दिन में की गई ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में विवरण मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र और दिल्ली के अधिकारी अगले तीन दिन में मुंबई के अधिकारियों से बात करें और उनसे प्राप्त अनुभवों के आधार पर ये आवश्यक कदम उठाएं। हम सोमवार को होने वाली सुनवाई में यह भी देखेंगे कि क्या ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए निष्पक्ष एक्सपर्ट के नेतृत्व में किसी वैज्ञानिक ऑडिट की ज़रूरत है। बता दें कि दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट मामले की लगातार सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही थी लेकिन अब बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

केंद्र सरकार के फॉर्मूले पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये पूरा फॉर्मूला सिर्फ अनुमान पर है। हर राय में स्थिति अलग हो सकती है। हर जिले में अलग हो सकती है। राय अलग-अलग वक्त पर पीक कर रहे हैं। ऐसे में आप सिर्फ एक ही तरह से नहीं हिसाब लगा सकते हैं। दिल्ली में इस वक्त हालात काफी खराब हैं। आपको हमें बताना होगा कि 3, 4, 5 मई को आपने क्या किया। केंद्र का कहना है कि उन्होंने 3 मई को 433 एमटी, 4 मई को 585 एमटी ऑक्सीजन दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र से सवाल किया कि आपने दिल्ली को कितना ऑक्सीजन दिया है। उन्होंने यह भी पूछा कि केंद्र ने हाईकोर्ट में ये कैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को 700 एमटी ऑक्सीजन सप्लाई का आदेश नहीं दिया। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि अप्रैल से पहले ऑक्सीजन की डिमांड यादा नहीं थी, लेकिन अब ये अचानक बढ़ी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि आदेश का पालन करे। नाकाम अफसरों को जेल में डालें या फिर अवमानना के लिए तैयार रहें, लेकिन इससे दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो काम करने से ही मिलेगी।

सुबह, शाम और दोपहर को केंद्र की ओर से मिले आंकड़ा

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र को हर सुबह, शाम और दोपहर को डाटा उपलब्ध कराना चाहिए। वर्चुअल कंट्रोल रूम का उपयोग होना चाहिए। किस अस्पताल को कितनी ऑक्सीजन मिल रही है, ये अस्पताल और लोगों सभी को पता होना चाहिए। जब दस तारीख को फिर से मामला सुनेंगे, तो राय सरकार की तैयारियों का जायजा लेंगे।

ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया कि दिल्ली की मांग अधिक है, उसके मुताबिक संसाधन की जरूरत है। अदालत में जस्टिस शाह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक राष्ट्रीय आपदा है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई है। केंद्र अपनी ओर से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी किल्लत है ऐसे में अपना प्लान हमें बताइए।

केंद्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मेरा सुझाव है कि एक कमिटी गठित हो, जिसमें निष्पक्ष विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। साथ ही इसमें केंद्र और दिल्ली के कुछ अधिकारी भी हों। यह कमेटी ऑक्सीजन की सप्लाई में आ रही दिक्कतों व परेशानियों को तुरंत सुधारने की ज़रूरत संबंधित रिपोर्ट सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करे।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारियों को जेल में डालने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिंदगियां बचें। जस्टिस चंद्रचूड़ ने राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर सुझाव दिया कि वैज्ञानिक तरीके से इसके वितरण की व्यवस्था करें। मुंबई में बीएमसी ने कोरोना काल में बढ़िया काम किया है ऐसे में दिल्ली को कुछ सीखना चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई नहीं करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि इस बात से हम अवगत हैं कि अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं। नोडल एजेंसी अधिकारी ने संक्रमित होते हुए भी कोर्ट को विस्तृत जानकारी दी थी। अधिकारियों को दंडित करने से कोई लाभ नहीं। कोर्ट ने शाम तक दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने के लिए ब्यौरा देने को कहा। कोर्ट ने कहा, हमें शाम तक बताइए कि दिल्ली में सप्लाई कैसे बढ़ेगी।

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अवमानना की प्रक्रिया शुरू की है, जबकि केंद्र व तमाम अधिकारी इस मामले में बेहतर काम कर रहे हैं। सॉलिसीटर जनरल ने मामला ष्छ्छ्ठ रमना के सामने रखा। उन्होंने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच मामला देखेगी।दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली समेत सभी रायों को किए जाने वाले ऑक्सीजन सप्लाई की निगरानी कर रहे अधिकारियों से आज सुनवाई के दौरान मौजूद रहने को कहा।

कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी, सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने दी चेतावनी

नई दिल्ली । सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के. विजय राघवन ने कहा कि भारत सहित दुनियाभर में इसके नए वैरिएंट सामने आएंगे। तमाम वैज्ञानिक इन अलग-अलग किस्मों का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं।

कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। इसे कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि, यह कब आएगी और यह कैसे इफेक्ट करेगी, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन, इसके लिए तैयार रहना होगा। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के. विजय राघवन ने यह चेतावनी दी है।

राघवन ने कहा कि कोरोना के नए वैरिएंट सामने आ रहे हैं। इन्होंने संक्रमण की रफ्तार बढ़ाई है। कोरोना के नए स्ट्रेन से निपटने के लिए वैक्सीन को भी अपडेट करने की जरूरत होगी।

राघवन के अनुसार, वैक्सीन कोरोना के मौजूदा वैरिएंट के खिलाफ कामयाब है। भारत सहित दुनियाभर में कोरोना के नए वैरिएंट सामने आएंगे। तमाम वैज्ञानिक इन अलग-अलग किस्मों का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं।

सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने कहा कि जिस तरह से यह वायरस बढ़ रहा है, उसे देखते हुए तीसरी लहर अपरिहार्य है। लेकिन, यह कब और किस पैमाने पर आएगी, इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 3,82,315 मामले दर्ज किए गए हैं। 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से यादा सक्रिय मामले हैं। 50,000 से 1,00,000 सक्रिय मामले 7 राज्यों में हैं। 17 रायों में 50,000 से कम सक्रिय मामले हैं।

लव अग्रवाल ने बताया कि रोजाना आधार पर कोविड के मामले करीब 2.4 फीसदी की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इस दौरान मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। देश में 24 राय और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 15 फीसदी से यादा पॉजिटिविटी रेट है। 10 रायों में 5-15 फीसदी पॉजिटिविटी रेट है। वहीं, 3 रायों में 5 फीसदी से कम पॉजिटिविटी रेट है।

अग्रवाल ने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में मौत के ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। कुछ जगहों को लेकर काफी चिंता है। बेंगलुरु में बीते हफ्ते कोरोना के करीब 1.49 लाख मामले देखने को मिले। चेन्नई में 38,000 मामले सामने आए। कुछ जिलों में कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं। इनमें कोझिकोड, एर्नाकुलम, गुरुग्राम शामिल हैं।

राहुल गांधी का केंद्र पर वार- न वैक्सीन न रोजगार, बिलकुल फेल मोदी सरकार!

नई दिल्ली । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीर स्थिति को लेकर बुधवार को एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि लोगों को टीका और रोजगार उपलब्ध कराने में मोदी सरकार नाकाम रही है।

उन्होंने ट्वीट किया, ना वैक्सीन, ना रोजगार, जनता झेले कोरोना की मार, बिलकुल फेल मोदी सरकार! राहुल गांधी कोरोना संकट को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि अब देश में संक्रमण जिस स्तर तक पहुंच गया है, वैसी हालत में सिर्फ लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है। सोमवार को भी कर्नाटक के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 24 मरीजों के मारे जाने को राहुल गांधी ने हत्या करार दिया था।

बता दें कि मंगलवार को देश में एक दिन में कोविड-19 से रिकॉर्ड 3,780 लोगों की मौत के बाद इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ कर 2,26,188 हो गई है जबकि एक दिन में संक्रमण के 3 लाख 82 हजार 315 नए मामले सामने आए हैं।

कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन की बर्बादी कम करना सबसे अहम : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देशभर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। एक मई से सरकार ने 18 उम्र को पार चुके लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन का रास्ता खोल दिया है और कई राज्य इस दिशा में काफी अच्छी काम कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को लेकर कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूत करने के लिए वैक्सीन की बबार्दी कम करना सबसे अहम है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट करते हुए वैक्सीन की बबार्दी रोकने के लिए केरल सरकार के प्रयासों की भी सराहना की है।दरअसल केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा था कि राज्य को केंद्र सरकार से टीकों की 73,38,806 खुराकें मिलीं और उपलब्ध अतिरिक्त खुराकों का भी इस्तेमाल करते 74,26,164 खुराकें दी गईं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्य के स्वास्थ्यकर्मियों, खासकर नर्सों की तारीफ की थी। इसी ट्वीट के जवाब में पीएम मोदी ने विजयन के ट्वीट को टैग करते हुए बुधवार को लिखा, टीकों की बबार्दी कम करने में हमारे स्वास्थ्यकर्मियों और नर्सों का उदाहरण प्रस्तुत करते देखना अच्छा लग रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए टीकों की बबार्दी कम करना महत्वपूर्ण है।उधर केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 रोधी टीके की 94.47 लाख से ज्यादा खुराकें हैं और उन्हें अगले तीन दिन में 36 लाख और खुराकें मिले जाएंगी। सुबह आठ बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, भारत सरकार ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अबतक टीके की 17,02,42,410 खुराकें मुफ्त मुहैया कराई हैं।

एक साल बाद एलएसी पर फिर बिगड़ सकते हैं हालात

सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है चीन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना का बीच हुई झड़प को एक साल बीत चुका है। डिसइंगेजमेंट और सैन्य सहमति की खबरों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात ठीक नहीं हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन अब गहरे इलाकों के साथ-साथ एलएसी पर भी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। पड़ोसी के इस कदम से सीमा पर हालात सामान्य होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं।

जैसे-जैसे क्षेत्र में सर्दियों का प्रभाव कम हो रहा है। वैसे ही चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एलएसी से 25 से 120 किमी अंदर तक अपने अस्थाई व्यवस्था को स्थाई करने का काम तेज कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चों पर पीएलए की नई टुकडियां नहीं आई हैं। लेकिन चीन ने तनाव वाले क्षेत्र में सैन्य शक्ति बढ़ाने के बीच बलों की अच्छी खासी संख्या को बरकरार रखा है। उन्होंने बताया, उदाहरण के लिए हाल ही के कुछ दिनों में रूटॉग कंट्री इलाके में काफी ज्यादा गतिविधि देखी गई है। यह इलाका पैंगोन्ग त्सो के मचान क्षेत्र के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि यह करीब 100 किमी की दूरी पर है। उन्होंने जानकारी दी पीएलए बेहतर सड़क और संपर्क के कारण तेजी से काम कर सकती है।

बीते साल 5-6 मी को पैंगोन्ग त्सो के उत्तरी किनारे पर चीनी और भारतीय सेना के बीच बड़ी झड़प हो गई थी। इसमें दर्जनों सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद 9 मई की उत्तरी सिक्किम के नाकू ला में भी इस तरह की घटना हुई थी। उस दौरान चीन ने अचानक क्षेत्र में अपने बलों की संख्या बढ़ा ली थी। इसके बाद भारत ने भी प्रतिक्रिया देते हुए तीन अतिरिक्त डिविजन्स को तैनात कर दिया था। हर डिविजन में 10 हजार से लेकर 12 हजार तक सैनिक मौजूद थे।

दोनों पक्षों के बीच 15 जून को गलवान घाटी में जमकर हिंसा हुई, जिसमें कई जवान शहीद हुए थे। हालांकि, कई कूटनीतिक और सैन्य वार्ता के बाद दोनों सेनाएं फरवरी में पैंगोन्ग त्सो से डिसइंगेजमेंट के लिए तैयार हो गई थीं। लेकिन तब से पीएलए ने गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, डेमचोक और देपसांग के मैदानों से हटने के लिए मना कर दिया था।

शपथ लेते ही ममता बनर्जी ने बंगाल में लगाया मिनी लॉकडाउन, लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर भी रोक

कोलकाता । पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में जहां लोकल ट्रेनों की आवाजाही भी रोकने का फैसला किया गया है तो दुकानें भी कुछ घंटों के लिए ही खुलेंगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच बंगाल में होने वाली चुनावी रैलियों को लेकर राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।

ममता बनर्जी ने पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा, कोविड-19 के हालात को देखते हुए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। मास्क पहनना अनिवार्य है तो राज्य सरकार के दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम कराने को कहा गया है, जबकि दफ्तर में 50 फीसदी ही कर्मचारी रह सकते हैं। शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जिम, सिनेमा हॉल्स, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। सामाजिक और राजनीतिक जुटान पर भी प्रतिबंध रहेगा।

ममता ने कहा कि जूलरी की दुकानें दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक खुलेंगी। होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा। बैंक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी बाजार, खुदरा दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक और फिर शाम 5 से 7 खुलेंगी।

6 मई से लोकल ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी। मेट्रो में क्षमता के 50 फीसदी लोग ही होंगे। 7 मई से राज्य के एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों को 72 घंटे भीतर का आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। जो लोग पॉजिटिव होंगे, उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। बस अड्डों पर रेंडम जांच की जाएगी तो यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा। ट्रेन यात्रियों पर भी यही नियम लागू होगा।

बिना टेस्ट रिपोर्ट के एयरपोर्ट पर एंट्री नहीं- वहीं कोविड संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए मेट्रो समेत सभी राज्य परिवहन के साधनों में 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ ही यात्री सवार हो सकेंगे. ममता सरकार के आदेश के मुताबिक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट (72 घंटे से कम अवधि की) के बिना हवाई अड्डे पर प्रवेश नहीं मिल सकेगा.

इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम करने के आदेश दिये गए हैं. राज्य में आभूषण की दुकानों को खोलने बंद करने का समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का होगा. इसके अलावा खाने का ऑनलाइन ऑर्डर और होम डिलिवरी को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके साथ ही बैंक में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम करने पर पाबंदी रहेगी.

ममता बनर्जी की पीएम नरेंद्र मोदी से फ्री वैक्सीन देने की मांग

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुभकामना देने पर धन्यवाद दिया है. इसके साथ ही विश्वास जताया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में मिलकर कोरोना महामारी का मुकाबला करेंगे. बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सीएम बनने पर ममता बनर्जी को ट्वीट कर धन्यवाद दिया था. इसके साथ ही ममता बनर्जी ने देश में सभी को फ्री वैक्सीन देने की मांग की है.

ममता बनर्जी ने सीएम पद की शपथ देने के बाद सीधे राज्य सचिवालय नबान्न पहुंचीं और वहां अधिकारियों के साथ कोरोना परिस्थिति को लेकर बैठक कीं. सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उन्हें बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया और सीएम ने ट्वीट कर भी इसकी जानकारी दी.

सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट- कोरोना से लड़ाई की जिम्मेदारी गडकरी को सौंपें पीएम मोदी, कारण भी बताया

नई दिल्ली । भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और रोजाना 3.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं. इसके अलावा देशभर के अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की किल्लत बनी हुई हैं. इस बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को कोरोना के खिलाफ लड़ाई की कमान परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सौंपने की सलाह दी है.

सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा, भारत कोरोना वायरस महामारी से बचेगा, जैसे उसने इस्लामिक और ब्रिटिश घुसपैठियों का मुकाबला किया, वैसे ही कोरोना का मुकाबला भी कर लेगा. अगर हम जरूरी कदम ना उठाएं तो हमें एक और लहर का सामना करना पड़ सकता है, जो बचों को अपने निशाने पर लेगी. पीएम नरेंद्र मोदी को ऐसे में इस लड़ाई की जिम्मेदारी नितिन गडकरी को देनी चाहिए. पीएमओ पर निर्भर रहना बेकार है.

पहले ऑक्सीजन को लेकर उठाए थे सवाल- इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर ऑक्सीजन का मुद्दा उठाया था. उन्होंने ट्वीट कर कहा था, सरकार को यह कहना बंद कर देना चाहिए कि कितना ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है. बल्कि यह कहना चाहिए कि कितनी हमने सप्लाई की है और किन-किन अस्पतालों में इसे भेजी गई है. पिछले साल अक्टूबर में ही स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ ने यह चेताया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर और सप्लाई की भारी किल्लत है. सरकार ने उसकी कोई परवाह नहीं की.

विरोधियों की भी प्रशंसा पाते हैं रोड बिल्डर गडकरी- स्वामी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलमपमेंट के अनुभव की जो बात की है, वो निराधार नहीं है। गडकरी ने सड़क निर्माण के इतने कार्य कराए हैं कि उन्हें रोड बिल्डर के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के तौर पर गडकरी ने 1995 से 99 के बीच राय में इतनी सड़कें बनाईं कि विपक्षी भी प्रशंसा करने को मजबूर हो गए। नागपुर के एनसीपी लीडर गिरीश गांधी ने कहा, ÷उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन का काम किया, वो अभूतपूर्व है। विदर्भ को इससे बहुत फायदा हुआ।÷ 1998 में महाराष्ट्र के तत्कालीन रायपाल सड़क मार्ग से अमरावती गए। वो सड़कों का काम देखकर इतने प्रभावित हुए कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को चिट्ठी लिखकर गडकरी की प्रशंसा की। मौजूदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे भी गडकरी के काम से काफी प्रभावित थे।

कार्टून

ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्ती घुसने पर 5 साल की सजा

मेलबर्न, (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया सरकार कोविड को लेकर बनाए अपने ही एक कानून को लेकर घिर गई है। चारों तरफ सरकार का विरोध हो रहा है। दरअसल, भारत में कोरोना की सुनामी के बाद दूसरे देशों की तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी सीमाएं भारत के लिए बंद कर दीं। 15 मई तक भारत आने-जाने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगाया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन 30 अप्रैल को सरकार ने 2015 के बायो-सिक्योरिटी एक्ट के तहत कानून बना दिया कि अगर भारत में फिलहाल रह रहे किसी भी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या रेजिडेंट ने ऑस्ट्रेलिया में दूसरे देश के रास्ते घुसने की कोशिश की, तो उसे 5 साल की सजा या 66,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर (करीब 37.5 लाख रुपए) का जुमार्ना भरना होगा। अब ऑस्ट्रेलिया मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को चिट्ठी लिखकर इस कानून पर ऐतराज जताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. उमर खुर्शीद के मुताबिक, भारत में फंसे लगभग 9 हजार ऑस्ट्रेलियाई बेहद खतरे में हैं।

उन पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सरकार को उन्हें किसी भी तरह वापस लाकर उनकी जान बचानी चाहिए। विपक्ष के नेता एंथनी एलबीसी ने तो मॉरिसन सरकार पर नस्लभेद का आरोप लगा दिया है। उनके मुताबिक, भारत में फंसे ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भारतीय मूल के हैं और एक साल से वापस आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पूरे विश्व में अभी 37 हजार से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई फंसे हैं।

दुनिया के सामने पहली बार आई काबा के काले पत्थर की अद्भुत तस्वीरें

रियाद, (एजेंसी)। सऊदी अरब सरकार ने पहली बार दुनियाभर के मुस्लिमों के पवित्र धर्मस्थल मक्का के प्राचीन काले पत्थरों की अद्भुत तस्वीरें दुनिया के सामने पेश की हैं। अल-हजर अल-असवाद या काले पत्थर की ये तस्वीरें 49 हजार मेगापिक्सल की हैं। सऊदी अरब की शाही मस्जिद और पैगंबर मस्जिद की ओर से जारी इन तस्वीरों को खींचने और बनाने में 50 घंटे लगे।

इस दौरान कुल 1050 फोटो लिए गए और प्रत्येक फोटो 160 गीगाबाइट का था। पत्थर की फोटो खींचने में ही 7 घंटे लग गए। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के इस्लामिक अध्ययन मामलों के शोधकर्ता अफीफी अल अकीती ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अप्रत्याशित है। उन्होंने कहा तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि यह वास्तव में काला नहीं है। ऐसा पहली बार है कि छोटे से काले पत्थर की हर चीज को बड़ा करके डिजटिल तस्वीर सामने आई है।

दुनियाभर के मुसलमानों के लिए मक्का बड़ा धार्मिक केंद्र है। मुस्लिम समुदाय में अगर किसी ने जन्म लिया है, तो उसके लिए जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा करना अनिवार्य माना जाता है। मुस्लिमों के पवित्र धर्मस्थल काबा पहुंचकर हज यात्री परिक्रमा करते हैं और काबा के पूर्वी कोने में लगे काले पत्थर को चूमते हैं। यह पत्थर देखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसका बहुत महत्व है। यह पत्थर चारों ओर से चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ है।

कहा जाता है कि यह काला पत्थर धरती पर आया धूमकेतु है। कुछ अन्य मान्यताओं में इसे चांद का टुकड़ा भी बताया जाता है। रोचक बात यह है कि काबा के जिस काले पत्थर को सबसे पवित्र माना जाता है, उसका जिक्र कुरआन में नहीं है। इसके पीछे यह धारणा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के धरती से जाने के बाद यह काला पत्थर अस्तित्व में आया। हालांकि हदीस में इस काले पत्थर का जिक्र किया गया है। कई हदीसों में इस पत्थर को जीवित बताया गया है। हज पर जाने वाले इस पत्थर को चूमकर खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं।

मैक्सिको सिटी में मेट्रो के पुल का एक खंभा ढह जाने से मलबे में दबकर 23 लोगों की मौत हो गई।

बोगाटो में किसी भी प्रदर्शन से निपटने के लिए तैयार सेना के टैंक सड़कों पर नजर आये।

चार जुलाई तक 70 प्रतिशत अमेरिकी वयस्कों को कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य : बाइडन

वाशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर एक नया लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत चार जुलाई से पहले 70 प्रतिशत अमेरिकी वयस्कों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक अवश्य दे दी जाएगी। राष्ट्रपति बाइडन इस समय टीके को लेकर सवाल खड़े करने वालों के अलावा उन लोगों से भी जूझ रहे हैं, जो वैक्सीन लगवाने को लेकर उत्साहित नहीं हैं। अमेरिका के अधिकांश प्रांतों में टीके की मांग में कमी देखी गई है।

कुछ प्रांत तो ऐसे हैं, जहां टीके की उपलब्ध खुराकों का इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा है। टीके को लेकर लोगों में उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से बाइडन ने विभिन्न प्रांतों से ऐसी व्यवस्था करने को कहा है, जिसमें टीकाकरण केन्द्र पर जाकर लोग सीधे टीका लगवा सकें। बाइडन प्रशासन ऐसी व्यवस्था कर रहा है जिसके तहत, जिन प्रांतों में टीके की मांग कम है, वहां से उनकी खुराकों को ऐसे प्रांतों में भेजा जाए जहां इसकी अधिक मांग है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस से युवाओं के लिए जारी अपने संदेश में कहा कि आपको टीका लगवाने की जरुरत है। यदि आपकी गंभीर रूप से बीमार पड़ने की संभावना कम हो, फिर भी खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। टीका लेने से आपकी और आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी जिंदगी बचाई जा सकती है।

बाइडन का लक्ष्य है कि चार जुलाई से पहले कम से कम 18.1 करोड़ वयस्कों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दे दी जाए, जबकि 16 करोड़ लोगों को दोनों खुराक दे दी जाएं। गौरतलब है कि अमेरिका में अब तक 56 प्रतिशत वयस्कों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि करीब 10.5 करोड़ वयस्कों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक दी जा चुकी है। अमेरिका में इस समय एक दिन में करीब 965,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है।

महामारी में 6.4 करोड़ महिलाओं ने नौकरी गंवाई

न्यूयार्क, (एजेंसी)। महामारी ने दुनिया भर की महिलाओं पर गंभीर असर डाला है। सबसे ज्यादा नुकसान नौकरीपेशा महिलाओं को हुआ है। महामारी की वजह से पिछले एक साल में दुनिया भर में 6.4 करोड़ महिलाओं को नौकरी गंवानी पड़ी, यानी हर 20 कामकाजी महिलाओं में से एक को। यह खुलासा बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन की हाल ही में जारी रिपोर्ट में हुआ है।

इसमें कहा गया है कि महिलाओं पर ज्यादा असर इसलिए पड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान महिला कर्मचारियों की अधिकता वाले रीटेल, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर पड़ा है।

इनमें करीब 40 फीसदी कर्मचारी महिलाएं हैं। वहीं स्कूल बंद होने की वजह से महिलाओं पर घर-परिवार और बच्चों की देखभाल का दबाव भी बढ़ा है। अब वे बच्चों की देखभाल में पिछले साल की तुलना में हर हफ्ते 31 घंटे गुजार रही है, जबकि पिछले साल यह हफ्ते के 26 घंटे था।

रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं की नौकरी को लेकर एक जैसा पैटर्न देखा गया है।

लगभग हर देश में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा नौकरी खोई है। इनमें कोलंबिया, कोस्टारिका, इक्वाडोर और चिली जैसे देशों में पुरुषों की तुलना में नौकरी गंवाने वाली महिलाओं की संख्या ज्यादा हैं। ऐसे शीर्ष-10 देशों में अमेरिका, कनाडा, स्पेन और ब्राजील भी हैं। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए 4 तरीके भी सुझाए गए हैं- डिजिटल मजबूती, कारोबार में मदद, नीति बनाते वक्त हर क्षेत्र की महिला का ध्यान रखा जाए, केयरगिविंग को भी नौकरीपेशा जैसी अहमियत मिले।

अफ्रीकी देश की महिला ने दिया 9 बच्चों को जन्म

माली, (एजेंसी)। अफ्रीकी देश माली की एक महिला ने मोरक्को में 9 बच्चों को जन्म दिया है। माली सरकार ने एक बयान जारी करके कहा कि मां और बच्चे सभी स्वस्थ हैं।

हालांकि अभी तक मोरक्को के प्रशासन ने इस घटना की पुष्टि नहीं की है। इससे पहले माली की सरकार ने 25 साल की हलीमा सिस्से को बेहतर देखरेख के लिए 30 मार्च को मोरक्को भेजा था। शुरू में यह माना गया था कि महिला के पेट में 7 बच्चे हैं। हालांकि उसने 9 बच्चों को जन्म दिया है। अब तक 6 बच्चों के एक साथ सफलतापूर्वक जन्म देने की घटना को दुर्लभ माना जाता था लेकिन अब महिला ने 9 बच्चों को जन्म दिया है।

इस बीच मोरक्को के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता राचिड कोउधारी ने कहा कि उन्हें देश के किसी अस्पताल में इतने बच्चों को जन्म देने की घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

उधर माली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हलीमा ने 5 बच्चियों और 4 बच्चों को सिजेरियन विधि से जन्म दिया है। देश की स्वास्थ्य मंत्री फांता सिबी ने कहा कि मां और बच्चे सभी अभी तक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि महिला के साथ माली के एक डॉक्टर भी गए हैं और वह पल-पल की जानकारी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि हलीमा और उनके बच्चों को अगले कुछ सप्ताह बाद वापस लाया जाएगा।

इस बीच स्थानीय मीडिया के मुताबिक डॉक्टरों ने हलीमा के स्वास्थ्य और बच्चों के जिंदगी को लेकर चिंता जताई है। माली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दोनों ही देशों में शुरू में हुए अल्ट्रासाउंड में पता चला था कि हलीमा के पेट में 7 बच्चे हैं। हालांकि उन्होंने कुल 9 बच्चों को जन्म दिया है। सिबी ने माली और मोरक्को की स्वास्थ्य टीम को इस सफल अभियान के लिए बधाई दी है।

भारत से डरबन पहुंचे मालवाहक पोत के चालक दल के सभी 14 सदस्य निकले कोरोना पॉजिटिव

जोहानिसबर्ग, (एजेंसी)। दक्षिण अफ्रीका में भारत से आए मालवाहक पोत के चालक दल के 14 सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। यह मालवाहक पोत भारत से दक्षिण अफ्रीका के डरबन आया। दक्षिण अफ्रीका की ट्रांसनेट नेशनल पोर्ट अथॉरिटी ने इस बात की जानकारी दी। ट्रांसनेट के प्रवक्ता ने बताया कि मालवाहक जहाज पर तैनात एक चीफ इंजीनियर की मौत कोविड-19 से नहीं, बल्कि दिल का दौरा पड़ने से हुई है।

रविवार को यह जहाज डरबन पहुंचा, जिसके बाद चालक दल के सभी 14 सदस्यों की जांच की गई जिसमें सभी संक्रमित पाए गए। चालक दल के सभी सदस्यों को पृथक-वास में रखा गया है और उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा रहा है। ट्रांसनेट ने कहा पूरे जहाज को पृथक-वास में रखा गया है और किसी को भी जहाज से बाहर जाने अथवा प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। यह कंपनी की जिम्मेदारी है कि इस पोत के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाया जाए।

बंदरगाह के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि पोत पर कम से कम 200 कर्मचारी काम कर रहे थे। रविवार शाम से ही जहाज से करीब तीन हजार टन चावल उतारने का काम किया जा रहा था। चावल 50-50 किलोग्राम की बोरियों में भरा हुआ था। इस खबर के कारण आशंका पैदा हो गई है कि भारत में कोरोना वायरस की भयावह लहर के लिए जिम्मेदार वायरस का बी.1.617 स्वरूप दक्षिण अफ्रीका में भी पहुंच चुका है।

दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री ज्वेली मखिजे ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जहाज के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत से आने वाली सीधी उड़ानों पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

रबड़ के डेंगू में ताइवान स्ट्रेट पार करने वाला चीनी घुसपैठिया गिरफ्तार

ताइपे, (एजेंसी)। ताइवान की पुलिस ने एक चीनी व्यक्ति को ताइवान स्ट्रेट में अवैध घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसने स्वतंत्रता और लोकतंत्र की तलाश में छोटे से रबड़ के डेंगू में अत्यधिक सैन्यीकृत ताइवान जलडमरूमध्य को पार कर लिया। पुलिस कप्तान के अनुसार शिओ झोउ नाम के व्यक्ति को चीन के पूर्वी तट पर फुज़ियान प्रांत से पानी की लगभग 80 किलोमीटर (50 मील) की दूरी पार करने के बाद ताइचुंग बंदरगाह के पास देखा गया था।

गौरतलब है कि दुनिया के सबसे सैन्यीकृत स्ट्रिप्स में से एक ताइवान स्ट्रेट को चीनी और ताइवानी दोनों नौसेनाओं द्वारा गश्त किया जाता है। हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग के आकलन के अनुसार, अकेले चीन के पास 255 से अधिक तटरक्षक जहाज और क्षेत्र में दर्जनों भारी-सशस्त्र नौसैनिक जहाज हैं। हालांकि ताइवान लोगों को आधिकारिक तौर पर शरण का दावा करने की अनुमति नहीं देता है और किसी को भी देश में अवैध घुसपैठ का दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल और 90,000 न्यू ताइवान डॉलर का जुमार्ना लगाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झोउ के खिलाफ ताइवान के राष्ट्रीय सुरक्षा और आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करने के लिए जांच की जा रही है।

हाल के महीनों में बीजिंग द्वारा स्व-शासित द्वीप के चारों ओर हवा और नौसैनिक अभ्यास शुरू करने पर ताइवान और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। कम्युनिस्ट पार्टी इसे अपने क्षेत्र का हिस्सा मानती है और इसने इसे चीन के साथ पुनः मिलाने की कसम खाई है। दूसरी ओर ताइपे ने अमेरिका सहित लोकतांत्रिक देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को बढ़ाकर चीनी आक्रामकता का मुकाबला किया है, जिसका बीजिंग द्वारा बार-बार विरोध किया गया है। चीन ने धमकी दी है कि ताइवान की स्वतंत्रता का मतलब युद्ध है। चीन ने हाल ही में तीन युद्धपोतों को चालू किया है, जिसमें एक बड़ा उभयचर हमला जहाज भी शामिल है, जो उन्हें दक्षिण चीन सागर को कवर करने वाले बेड़े में जोड़ता है।

दुनिया में शाकाहार की तरफ बढ़ा रुझान

न्यूयार्क, (एजेंसी)। दुनिया के रईसों में मशहूर मैनहट्टन (न्यूयॉर्क) के इलेवन मेडिसन पार्क रेस्तरां ने अपने मेन्यू में बड़ा बदलाव किया है। रेस्तरां अब मीट और सी-फूड सर्व नहीं करेगा। कोविड महामारी के बाद हाल ही में दोबारा खुले रेस्तरां ने इस बदलाव का फैसला किया है। चीफ शेफ डेनियल हम ने कहा है कि बीते 18 महीनों में हमने काफी कुछ देखा-सुना और समझा है। मीट और सी-फूड को लेकर कई पर्यावरणविदों और सामाजिक संस्थाओं ने कहा है कि महामारी फैलने की वजहों में एक ग्लोबल फूड सिस्टम की कमजोरी और खासकर नॉनवेज भोजन से होने वाले खतरों को नजरअंदाज करना है। हालांकि मैडिसन पूरी तरह से जानवरों से मिलने वाली खाद्य सामग्री से दूर नहीं होगा। दूध, अंडे, शहद वाली चाय पहले की तरह सर्व होती रहेंगी। डेनियल के मुताबिक, नए मेन्यू में हमारा सबसे ज्यादा फोकस हरी सब्जियों और प्राकृतिक उत्पादों पर होगा। हमें भरोसा है कि ग्राहक भी इसे पसंद करेंगे क्योंकि ये अब समय की जरुरत है। दूसरी ओर, मैडिसन पार्क के मेन्यू में हुए बदलावों पर दूसरे बड़े रेस्तरां और फूड स्टेशनों को भी ये आइडिया पसंद आया है। न्यूयॉर्क सिटी के वेज रेस्तरां डर्टी कैंडी की मालकिन अमांडा कोहेन कहती हैं, हम का निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पहले भी संयंत्र आधारित व्यंजनों से नहीं जुड़े थे। उनका कदम हमें भी आगे की राह दिखाता है।

नेबल्स में गोलीबारी में शामिल संदिग्ध फिलिस्तीनियों की तलाश करते हुए इजरायली सैनिक।

शिनजियांग मसले पर पीएम जेसिंडा ने चीन पर साधा निशाना

वेलिंगटन, (एजेंसी)। चीन में मानवाधिकारों के मुद्दे पर न्यूजीलैंड अब अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया आदि देशों के साथ आता दिखाई दे रहा है। उइगर मुस्लिमों को लेकर चीन के बारे में न्यूजीलैंड के तेवर भी अब बदल रहे हैं। ऑकलैंड में चाइना बिजनेस मीट में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा ने कहा कि उन्होंने चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगरों के मानवाधिकारों के हनन पर गंभीर चिंता से अवगत करा दिया है। उनकी चिंता हांगकांग में रहने वाले लोगों के लिए भी है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में तमाम ऐसे मामले हैं जिनको वैश्विक स्तर पर सुलझाने में मुश्किल हो रही है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने शिनजियांग में मानवाधिकारों को लेकर चीन पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि चीन की विश्व में बढ़ती उपस्थिति के बीच उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड के कारण मतभेदों को सुलझाना मुश्किल हो रहा है। प्रधानमंत्री जेसिंडा की अक्सर अन्य नेताओं की तुलना में भाषा और संदेश अक्सर सीधे तौर पर नहीं होते हैं। वे अब तक चीन की आलोचना करने से बचती रही हैं। जेसिंडा का ताजा बयान उनकी चीन को लेकर बदलते तेवर का संकेत देता है।

दरअसल शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों को यातना दिए जाने की सच्चाई निया में सामने आने के बाद अब चीन झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है। उसने उइगरों पर एक डॉक्यूमेंटरी बनाकर यह फैलाने की कोशिश शुरू कर दी है कि शिनजियांग में सब कुछ ठीक है। उइगर वहां खुशहाल हैं। चीन की इस वीडियो पर उइगर कार्यकताओं ने कहा है कि यह झूठी वीडियो हैं। अपने ऊपर लगे कलंक को चीन ऐसी वीडियो से मिटा नहीं पाएगा। उइगर के अधिकारों के लिए लड़ने वाले फरंगिस नजीबुल्लाह ने कहा कि चीन अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उइगरों के मामले में भटकाने का प्रयास कर रहा है। चीन ने शिनजियांग पर एक डॉक्यूमेंटरी द माउंटेंस- लाइफ ऑफ शिनजियांग बनाई है। इसमें शिनजियांग के उइगरों के साक्षात्कार लिए हैं, जो कह रहे हैं कि वे यहां बहुत खुश हैं। इस डॉक्यूमेंटरी को कई भाषाओं में बनाने से चीन का मकसद साफ दिखाई दे रहा है कि वह वास्तविकता से अलग झूठा प्रचार कर अपनी छवि को साफ करने की कोशिश कर रहा है।

ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस ने शख्स को किया अरेस्ट

(आनंद राय)

नई दिल्ली । दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स के साथ-साथ जीवन रक्षक दवाओं और ऑक्सीजन आदि की भी भारी किल्लत हो रही है. इसके चलते इन सभी चीजों की ब्लैक मार्केटिंग का गोरखधंधा भी शुरू हो गया है. इस पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है. सूचना मिलने पर लगातार छापेमारी भी कर रही है.

दिल्ली पुलिस ने एक सूचना के आधार पर लाहौरी गेट थानांतर्गत इलाके में छापेमारी कर पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले शख्स को धर दबोचा है.

पुलिस के मुताबिक उत्तरी जिला पुलिस के

लाहौरी गेट थाने की टीम ने उंची कीमतों पर दो ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है.

जिला पुलिस उपायुक्त एन्टो अल्फोन्स ने बताया कि 3 मई को, कोविड सेल, पीएचक्यू ने उत्तरी जिले को एक शिकायत भेजी थी जिसमें कॉल करने वाले ने टेलीफोन पर सूचना दी है कि नॉवल्टी सिनेमा हॉल के पास एक ऑक्सीजन सप्लायर एमआरपी की तुलना में बहुत अधिक रेट पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहा है.

इसके बाद एसआई संदीप माथुर ने खुद को ग्राहक बताकर उक्त मोबाइल पर फोन किया. बातचीत के दौरान, संदिग्ध दो 12 लीटर पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर को 3,600/- रुपये में बेचने के लिए तैयार हो गया. व्यक्ति ने एसआई संदीप माथुर के मोबाइल पर उक्त वस्तु की फोटो भी भेजी और एसपीएम मार्ग पर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए तैयार हो गया.

इसके बाद एसीपी कोतवाली उमा शंकर की देखरेख में एसएचओ लाहौरी गेट जरनैल सिंह के निर्देश पर एसआई संदीप माथुर, एएसआई दीपक, हैड कांस्टेबल समंदर, कांस्टेबल दीपक और करण की टीम ने एसपीएम मार्ग पर अपना जाल बिछाकर करीब 5.50 बजे, संदिग्ध गुरविंदर सिंह (26) को दो ऑक्सीजन 12 लीटर सिलेंडर के साथ पकड़ लिया. एसआई संदीप माथुर ने ऑक्सीजन सिलेंडर की जाँच की और पाया कि एमआरपी मिटा हुआ था. उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर इसकी एमआरपी चेक की तो कीमत 450/- रुपये मिली. तुरंत, टीम ने संदिग्ध को पकड़ लिया. पुलिस ने उससे स्वामित्व बिल, डॉक्टर के पर्चे की पर्ची, बिल आदि के बारे में पूछा गया. लेकिन वह कोई संतोषजनक कारण नहीं बता सका. पुलिस पूछताछ में गुरविंदर ने बताया कि वह पेशे से बिजली मिस्त्री है. उसे गाजियाबाद से 06 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले थे जिसमें से चार अन्य को बेच दिए थे और अब 2 उसके पास थे.

अब घर बैठे एनडीएमसी की 49 सेवाओं का ले सकते हैं लाभ, जानिए कौन कौन सी हैं सेवाएं

नई दिल्ली । कोरोना के चलते नागरिक घर बैठे ही आनलाइन सुविधाएं ले सकें इसके लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने सिंगल साइन आन (एसएसओ) तकनीक को लागू कर दिया है। यानि निगम की 49 सेवाएं अब आनलाइन मिलेगी। वहीं, इसके लिए अलग-अलग यूजर आइडी और पासवर्ड बनाने की जरुरत नहीं होगी। एक बार बनाए गए यूजर आइडी से ही बिजली-पानी और संपत्तिकर से लेकर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा। पहले एनडीएमसी के 45 सेवाएं आनलाइन थी, जिसे बढ़ाकर 49 कर दिया है।

वही, सभी को अब एसएसओ तकनीक से जोड़ दिया है। एनडीएमसी के आइटी विभाग के निदेशक डीपी सिंह ने बताया कि दिल्ली में एनडीएमसी पहला निकाय हैं जिसने यह व्यवस्था लागू कि है।उन्होंने कहा कि देश में बहुत कम सरकारी संस्थानों ने ऐसी सुविधा नागरिकों को दी है। जहां एक ही यूजर आइडी और पासवर्ड से विभिन्न सेवाओं को लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि चूंकि अभी लाकडाउन के चलते एनडीएमसी के दफ्तर भी बंद हैं।

वहीं, कोरोना में लोगों को कम से कम ही घर से निकलने की सलाह दी जाती है। इसको देखते हुए एनडीएमसी ने सभी नागरिक सेवाओं को आनलाइन करते हुए उसे एसएसओ तकनीक से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि न केवल नागरिकों को बल्कि निगम के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए पेंशन संबंधी दी जाने वाली सुविधाएं भी आनलाइन हैं। जिसका वह घर बैठे लाभ उठा सकते हैं।

संक्षिप्त खबर

दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में कुछ कमी, 19, 953 नए मामले और 338 लोगों की हुई मौत

नई दिल्ली । दिल्ली में कोरोना से हालात कुछ सुधार देखे जा रहे हैं. दिल्ली सरकार ने मंगलवार का हेल्थ बुलेटिन बुधवार सुबह जारी किया है. इस बुलेटिन में नए केस और मौत दोनों में कमी दिखाई गई है. मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 19, 953 नए मामले सामने आए हैं और 338 लोगों की मौत हुई है. अब दिल्ली में एक्टिव संक्रमित मरीजों की संख्या 90, 419 हो गई है. मंगलवार को 18, 788 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है. इस समय दिल्ली में 49, 829 लोग होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं, जबकि मंगलवार को कोरोना के 74, 654 सैंपल की जांच हुई है. दिल्ली में मृत्यु दर के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं. मंगलवार को भी मृत्यु दर 1.44 त्न रहा. अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो बीते तीन दिनों से 30 प्रतिशत के नीचे रह रही है. मंगलवार को भी पॉजिटिविटी रेट 26.73 प्रतिशत था.

पिछले चार दिनों के आंकड़े क्या कहते हैं- बता दें कि दिल्ली में सोमवार को 18, 043 नए मामले सामने आए थे और 448 लोगों की मौत हुई थी. रविवार को भी कोरोना के नए मामले में कमी आई थी, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार 400 के पार रह रहा है. दो सप्ताह के बाद पहली बार रविवार को पॉजिटिविटी रेट 30 प्रतिशत से नीचे आया था. रविवार को पॉजिटिविटी रेट 28.33त्न रहा. वही सोमवार को पॉजिटिविटी दर 29.56 प्रतिशत था.

गरीब परिवारों और ऑटो-टैक्सी चालकों को मदद करेगी- वहीं, मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे गरीब परिवारों और ऑटो-टैक्सी चालकों की मदद करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार 72 लाख राशन कार्ड धारकों को दो महीने तक मुफ्त राशन देगी. साथ ही पिछले साल की तरह ही इस बार भी दिल्ली में पंजीकृत 1.56 लाख ऑटो-टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी.

मुफ्त राशन देने का मतलब यह नहीं – सीएम ने स्पष्ट किया कि दो महीने तक मुफ्त राशन देने का मतलब यह नहीं है कि दिल्ली में लॉकडाउन भी दो महीने चलेगा. कोरोना के केस कम होते ही लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा. सीएम ने कहा कि यह समय एक-दूसरे की मदद करने और अच्छा इंसान बनने का है. मैं अपील करता हूं कि सभी पार्टी और जाति-धर्म के लोग एक-दूसरे की मदद करें. हम लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने, ऑक्सीजन व बेड दिलाने, बीमार और गरीब लोगों को खाना खिलाने में मदद कर सकते हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर लड़ेंगे तो बहुत जल्द कोरोना से जीत पा लेंगे. कोरोना के केस में कमी लाने और इसकी चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी था.

शुतुरमुर्ग की तरह आप रेत में सिर धंसाइये, हम ऐसा नहीं कर सकते दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई लताड़

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में जारी ऑक्सीजन संकट के बीच इस मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई भी जारी है। आक्सीजन आपूर्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर भी कार्रवाई नहीं होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार को जमकर सुनाया। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर रेत में धंसा सकती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। पीठ ने कहा कि हर दिन हम अस्पताल और नर्सिंग होम की स्थितियों को देख रहे हैं। स्थिति यह है कि अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं जबकि आक्सीजन नहीं मिलने से अस्पताल लगातार अपने यहां बिस्तरों की संख्या कम कर रहे हैं। पीठ ने फैसले में कहा कि हमें दुख है कि आक्सीजन आपूर्ति के मामले को केंद्र सरकार द्वारा जैसे देखा चाहिए था, उसने नहीं देखा।

आप अंधे हो सकते हैं हम नहीं हैं- सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने पीठ से कहा कि सालिसिटर जनरल ने कहा था कि सिर्फ दिल्ली को ही आक्सीजन की समस्या है। हालांकि मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं। एएसजी द्वारा दिल्ली को आपूर्ति करने की दलील पर राहुल मेहरा ने कहा कि आप 420 मीट्रिक टन आपूर्ति कर रहे हैं और लोग मर रहे हैं। मेहरा की दलील को वाकपटुता बताने पर पीठ ने एएसजी चेतन शर्मा को आड़े हाथ लिया। पीठ ने कहा कि यह वाकपटुता नहीं है, यह हकीकत है और मेहरा ने कोई गलत दलील नहीं दी है। पीठ ने कहा कि माफ करिए एएसजी शर्मा आप अंधे हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं है। आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं।

मरीजों की मौत और विभिन्न मुद्दों पर पीठ द्वारा की गई कई तल्ख टिप्पणी पर एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि हमें भावनात्मक होने की जरूरत नहीं है। इसके जवाब में पीठ ने कहा कि लोगों की जान खतरे में है और यह भावनात्मक मामला है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुई अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी ने पीठ से कहा कि हम टैंकर और आपूर्ति का पूरा डाटा पेश करेंगे। उन्होंने बताया कि रेलवे और एयरक्राफ्ट के माध्यम से आपूर्ति हर दिन के हिसाब से तय होती है। जबकि एएसजी ने बताया कि 138 क्रायोजेनिक टैंकर का आयात किया गया है। इसके जवाब में पीठ ने कहा कि आप क्या योजना बना रहे हैं और भविष्य में क्या करेंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन आज पूरा देश आक्सीजन के लिए रो रहा है। पीठ ने कहा कि आप विशेषज्ञों को शामिल करिए और आइआइएम के ब्रिलियंट माइंड को इस काम में लगाइए।

गुजरात से दिल्ली पहुंची दो और 'ऑक्सीजन एक्सप्रेस', रेल मंत्री पीयूल गोयल ने दी जानकारी

नई दिल्ली । कोरोना के खिलाफ देश की जंग जारी है. इस बीच सरकार राज्यों को संजीवनी बनी ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिशों में जुटी हुई है. केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए टाटानगर से एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस फरीदाबाद पहुंच चुकी है. इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल अलग-अलग अस्पतालों में कोविड के उपचार के लिए किया जाएगा. वहीं पीयूष गोयल ने एक और ट्वीट में बताया है कि ऑक्सीजन टैंकर से भरी एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस गुजरात के मुंद्रा से दिल्ली पहुंच चुकी है. इसके अलावा गुजरात के हपा से भी एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली कैंट पहुंची है. दरअसल कोरोना के चलते दिल्ली हालत इस वक्त बेहद खराब है. ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं जबकि कई लोगों की जान अभी भी खतरे में हैं. ऐसे में एक के बाद एक ऑक्सीजन एक्प्रेस दिल्ली पहुंच रही हैं. इससे पहले खबर आई थी कि केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी का दैनिक ऑक्सीजन कोटा 490 मिट्रिक टन से बढ़ाकर 590 मिट्रिक टन कर दिया. केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, दिल्ली को ओडिशा के कलिंग नगर से अतिरिक्त 75 मिट्रिक टन और ओडिशा के झारसुगुडा की जेएसडब्ल्यू बीपीएसएल से 25 मिट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी.

विधायक ने लगाये सरकार पर आरोप, कहा- वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नहीं मूलभूत सुविधाएं, पीने का पानी तक नहीं

नई दिल्ली । कोरोना की रोकथाम के लिए तीसरे चरण के तहत 18 साल से अधिक की उम्र के लोगों के लिये अब तीसरे चरण का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है. दिल्ली सरकार की ओर से अब तक 33,93,467 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है. वहीं, तीसरे चरण के लिए बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटरों में स्वास्थ्य कर्मियों को मुहैया कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर विधायक दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े करने लगे हैं.

विधायक आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार की ओर से बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटरों में स्टाफ के लिए पीने के पानी से लेकर शौचालय आदि की समस्या को भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है.

अब तक दी जा चुकी है 33,93,467 को कोरोना की डोज – बताते चलें कि मंगलवार को भी पिछले 24 घंटे में 89,297 लोगों को कोरोना वैक्सीन के डोज दिए गए. इनमें पहली डोज वालों की संख्या 61,662 रिकॉर्ड की गई. वहीं 27,635 को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई. अब तक पहली डोज लेने वालों की संख्या 26,54,809 हो चुकी है. वहीं,

दूसरी डोज लेने वालों का आंकड़ा 7,38,658 हो चुका है. अब तक 33,93,467 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है.

रोहताश नगर के विधायक जितेंद्र महाजन ने दिल्ली सरकार पर कोरोना काल में टीकाकरण कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं देने का आरोप लगाया है.

महाजन के अनुसार ये स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय आदि अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं. मगर दिल्ली सरकार इन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे रही है.

पिछले 15 मार्च से रोहतास नगर विधानसभा के दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के वेलकम स्थित समुदाय भवन परिसर में टीकाकरण चल रहा है. लेकिन इस समुदाय भवन परिसर में पानी का कोई प्रबंध नहीं है. स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ना तो पीने का पानी है और ना ही शौचालय में पानी की कोई व्यवस्था है. महिला स्वास्थ्य कर्मियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

विधायक जितेंद्र महाजन के अनुसार DUSIB अधिकारियों को कई बार शिकायत करने के बाद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है. दूसरी ओर मानसरोवर पार्क के गवर्नमेंट स्कूल में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है. मगर यहां पर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीने के पानी तथा पूरे दिन में किसी भी प्रकार के जलपान की कोई व्यवस्था नहीं है. महाजन ने दिल्ली सरकार से मांग की कि इन सभी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं.

कोरोना के बढ़ते केस पर बोले संदीप दीक्षित दीक्षित- अरविंद केजरीवाल सरकार पर दर्ज हो हत्या का मामला

नई दिल्ली । दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर हैं। इस कड़ी में पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने कोरोना संकट को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। मंगलवार को एक वीडियो संदेश जारी करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर दिल्ली को एक मजबूत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली नहीं देने के लिए हत्या का मामला चलाया जाना चाहिए।

उन्होंने दावा किया कि शीला दीक्षित की सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में बेड की संख्या चार हजार से बढ़ाकर 11 हजार कर दी थी, लेकिन केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में कोई बेड नहीं जोड़ा गया। अरविंद केजरीवाल हर बात के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हैं, लेकिन अपने गिरेबां में नहीं देखते कि खुद क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार ने जो 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए फंड जारी किया, उसका कहां इस्तेमाल हुआ केजरीवाल

सरकार बताए?

उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे आइटीबीपी और डीआरडीओ ने बहुत कम समय में अस्पतालों की स्थापना की है, लेकिन दिल्ली सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपना समय और देश का पैसा प्रचार में बर्बाद किया है।

संदीप दीक्षित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी संकट के समय में दिल्ली पर पर्याप्त ध्यान नहीं देने का अरोप लगाते हुए कहा कि जब राहुल गांधी को पता था कि कोरोना की सुनामी आ रही है तो पीएम मोदी और उनकी सरकार को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। अगर इससे निपटने की पूर्व तैयारी कर ली गई होती तो हालात इतने खराब नहीं होते।

दिल्ली के इन दो अस्पतालों में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट, 1000 लीटर प्रति मिनट की फ्लो रेट से होगी सप्लाई

नई दिल्ली । कोरोनावायरस की वजह से कराह रहे पूरे देश में ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत हो गई है. ऑक्सीजन न मिलने की वजह रोजाना कई मरीज दम तोड़ रहे हैं. देश के अलग-अलग राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए हरसंभव कोशिश की जा रही है. राजधानी दिल्ली में तो ऑक्सीजन की भारी कमी है. दिल्ली के कई अस्पताल लगातार ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली में रोजाना 976 मिट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और सोमवार को उन्हें सिर्फ 433 मिट्रिक टन ऑक्सीजन ही प्राप्त हुई थी.

बुधवार शाम से शुरू हो जाएगी ऑक्सीजन की सप्लाई- राजधानी में ऑक्सीजन की मौजूदा जरूरत को देखते हुए दिल्ली के एम्स अस्पताल और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कुल दो हाई कैपेसिटी मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं. ये ऑक्सीजन प्लांट बुधवार शाम से मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर देंगे. बताते चलें कि दिल्ली के अस्पतालों में लगाए गए ये दोनों हाई कैपेसिटी ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर्स फंड की मदद से लगाए गए हैं. जानकारी के मुताबिक ये मेडिकल ऑक्सिजन प्लांट्स 1000 लीटर प्रति मिनट की फ्लो रेट के लिए डिजाइन किए गए हैं. एम्स और आरएमएल में लगाए गए ये प्लांट्स निश्चित रूप से ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतों को दूर कर आपातकाल में कोरोना मरीजों को नई जिंदगी प्रदान करेंगे.

ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए दिन-रात काम कर रही रेलवे, वायुसेना और नौसेना बता दें कि केंद्र सरकार पीएम केयर्स फंड से देशभर में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऐलान किया था. ऑक्सीजन प्लांट के अलावा देशभर में जरूरतमंद राज्यों को भारतीय रेल की मदद से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है. रेलवे के अलावा भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना भी जरूरतमंद राज्यों में दिन-रात ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है.

दिल्ली में ऐसी भी कॉलोनी, यहां लोगों को कोरोना टीका लगवाने के लिए मना रहे हैं अधिकारी

नई दिल्ली । कोरोना की मार से कराह रही दिल्ली में जहां एक तरफ बेड की कमी है लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, वहीं एक कॉलोनी ऐसी भी जहां लोगों को टीका दिलाने के लिए अधिकारी मान मनौवल करने में लगे हैं. यही नहीं दिल्ली सरकार ने अपने पुराने नियम में बदलाव करके अलग से इनके लिए कैंप लगाया है. दास्तान है दिल्ली के कठपुतली कॉलोनी के 2800 परिवार की.

जी हां, यह कहानी है दिल्ली की कठपुतली की. कॉलोनी जो अब डीडीए की ट्रांजिट कैंप के तौर पर जानी जाती है, यहां तकरीबन 2800 परिवार है, जिनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पास में ही फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं. लेकिन, यहां रहने वालों लोगों की परेशानी की दास्तान बहुत पुरानी है. इनमें से ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड भी नहीं है. मतदाता पहचान पत्र भी नहीं है. दूसरी सबसे बड़ी परेशानी यहां के लोगों को समझाना भी मुश्किल रहा.

पहचान पत्र की भी मुसीबतें हैं- दिल्ली सरकार ने पश्चिमी दिल्ली जिला प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी दी. प्रशासन ने अपने ह्रस्ठ इशान शर्मा को जिम्मेदारी सबसे पहले इन लोगों को टीकाकरण के बारे में समझाने की कोशिश की. इसके लिए ष्ठष्ठ के ट्रांजिट कैंप इंचार्ज संजय गौड़ के साथ मिलकर यहां के 14 समुदाय के नेताओं के साथ बैठक की हुई. इसमें पूरण भट्ट जैसे कलाकार भी रहते हैं, जिन्हें कठपुतली के खेल के लिए कई राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जा चुका है. यहां कई राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार रहते हैं

पश्चिमी जिला प्रशासन के जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर रंजना कक्ड ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह कर दिल्ली के पहली आउटरीच साइट बनाने परमिशन लिया क्योंकि किसी सरकारी डिस्पेंसरी या स्कूल में कैंप लगाया जा सकता था, लेकिन जिला प्रशासन को कैंप लगाने की अनुमति मिली और 45 साल से अधिक के लिए सोमवार से टीकाकरण अभियान शुरू हो गया.

दिल्ली के IPL क्रिकेट मैच में विनोद भट्ट की टीम ढोल बजाकर आई

OSD इशान शर्मा ने बताया कि यहां रहने वाले 22000 हजार लोगों की कार्यप्रणाली को देखते हुए इसे सुपर स्प्रेडर माना जा सकता है क्योंकि ज्यादा कलाकार काम के लिए दिल्ली के अलग-अलग इलाके में जाते हैं, जैसा कि अभी आईपीएल में भी ढोल बजाने के लिए यहां के निवासी विनोद भट्ट की टीम गई है. बहरहाल इनमें से ज्यादातर लोग आस पास के वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब यहां इनके लिए एक कैंप लगाया गया है. उसमें लोगों को बुला-बुलाकर टीका लगाया जा रहा है. कैंप में पहले दिन तो सिर्फ 50 लोग ही आए, लेकिन दूसरे दिन संख्या काफी उत्साह जनक रही.

जागरूक करने के लिए कई उपाय किए- कैंप तक लाने के लिए ढोल बजाए गए. मस्जिदों से अजान के बाद घोषणाएं कराई गईं. नुक्कड़ नाटक भी हुआ, लेकिन खास असर नहीं पड़ा. दिल्ली में 45 साल से ऊपर के लोगों के टीकाकरण के लिए ज्यादातर सेंटर्स सरकारी डिस्पेंसरी में बनाए गए हैं, जबकि 18 से 44 साल के लिए 77 स्कूलों में ही टीकाकरण की व्यवस्था की गई है.

किन अव्यवस्थाओं की वजह से राजधानी के सरकारी और निजी अस्पतालों में बनी रही ऑक्सीजन की कमी, सिलेंडरों पर रहे निर्भर

नई दिल्ली । कोरोना वायरस के संक्रमण से दिल्लीवासियों को बचाने के लिए बने कोविड अस्पताल खुद अव्यवस्थाओं के संक्रमण से जूझ रहे हैं। महामारी के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही जा रही है। हालत यह है कि कोरोना संक्रमण से पीड़ित गंभीर मरीजों के इलाज के लिए अधिकृत दर्जनों सरकारी व निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन के स्टोरेज व सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई तक की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से ये अस्पताल ऑक्सीजन सिलेंडर पर ही निर्भर हैं। निजी क्षेत्र के ज्यादातर छोटे अस्पतालों में यही स्थिति है।

अब जब अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाने के कारण होम आइसोलेशन में रह रहे गंभीर मरीज घर में ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे रहने को मजबूर हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी का सामना करना पड़ा रहा है। छोटे अस्पतालों में ही ऑक्सीजन की समस्या अधिक है। कई बड़े निजी अस्पतालों में भी अभी जरूरत से कम आक्सीजन आपूर्ति हो रही है, हालांकि स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। सफदरजंग, आरएमएल, जीटीबी, राजीव गांधी

सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल व एम्स में आक्सीजन स्टोरेज की अच्छी व्यवस्था तो है, लेकिन इन अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए कम बेड आरक्षित किए गए हैं।

हालांकि, एम्स ने ट्रामा सेंटर में 294, मुख्य अस्पताल में 164 बेड की व्यवस्था करने के अलावा झज्जर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (एनसीआइ) में करीब 570 बेड की व्यवस्था की है। इस तरह एम्स में करीब 1,028 बेड की व्यवस्था है, लेकिन दिल्ली एम्स के मुख्य अस्पताल के परिसर में इतने संसाधन हैं कि एम्स प्रशासन चाहे तो और बेड बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं, जीटीबी अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए अधिकृत बेड 1,500 से घटाकर 750 व राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में 500 बेड से घटाकर 350 बेड आरक्षित किए गए हैं।

वहीं, राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के करीब हर बेड पर सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की सुविधा है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी का हवाला देकर अस्पताल प्रशासन ने बेड कम कर दिए हैं। करीब 1,500 बेड की क्षमता वाले आरएमएल अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए महज 263 बेड निर्धारित हैं। करीब 2,800 बेड की क्षमता वाले सफदरजंग अस्पताल के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में कोविड मरीजों के लिए सिर्फ 275 बेड ही निर्धारित हैं। आरएमएल अस्पताल के एक वरिष्ठ डाक्टर ने कहा कि अस्पताल में गैर कोरोना मरीजों का भी इलाज हो रहा है, फिर भी कोरोना के इलाज के लिए जल्द 200 बेड जल्द बढ़ाया जाएगा।

वहीं, सफदरजंग अस्पताल के एक डाक्टर ने बताया कि यहां भी बेड बढ़ाने की कवायद चल रही है।

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डा. अजय लेखी कहते हैं कि ज्यादातर बड़े अस्पतालों में भी सभी बेड पर सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। ऑक्सीजन आपूर्ति की क्षमता के अनुसार ही अस्पतालों ने कोरोना के लिए बेड आरक्षित किए हैं, लेकिन इस महामारी के मद्देनजर यह जरूरी है कि अस्पतालों के सामान्य वार्ड में भी सभी बेड पर सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा अस्पतालों में आइसीयू बेड भी बढ़ाने पड़ेंगे। करीब 150 की क्षमता वाले निजी क्षेत्र के रैनबो अस्पताल में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन नहीं है।

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अस्पताल के भवन के नीचे से मेट्रो की लाइन गुजरती है इस वजह से ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट की व्यवस्था करना संभव नहीं है। अस्पताल को ऑक्सीजन सिलेंडर से ही काम चलाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के जनकपुरी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भी सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की सुविधा नहीं होने की वजह सिर्फ 14 बेड कोरोना के इलाज के लिए आरक्षित हैं, जबकि इन्हें बढ़ाकर 100 तक किया जा सकता है।

अगले 3 दिन तक के मौसम का हाल, कहां होगी बारिश और कहां आएगी आंधी

नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, बुधवार शाम को मौसम के करवट लेने के आसार हैं। इसके बाद तेज हवा चलेगी। इसके बाद बृहस्पतिवार से धूल भरी आंधी के साथ दो दिन हल्की बारिश का दौर भी चलने की संभावना है। इससे गर्मी से भी कुछ राहत मिली। मौसम विभाग का पूर्वानुमान के मुताबिक, बुधवार सुबह से ही आंशिक तौर पर बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही शाम तक गर्जन वाले बादल बनने और 30 से 40 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवा चलने की संभावना है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 40 और 25 डिग्री रह सकता है।

वहीं स्काईमेट वेदर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में पहले से ही मध्यम बारिश और गरज के साथ दस्तक दे रहा है। हमेशा की तरह, साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक या दो दिन तक रहता है। इसके बुधवार को हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में पहुंचने की उम्मीद है। जबकि दिल्ली को इस मौसमी गतिविधि के लिए एक और दिन का इंतजार करना होगा। यहां यह मौसमी गतिविधि बृहस्पतिवार और शुक्रवार को जारी रहेगी। संभावना जताई जा रही है कि यह शनिवार को भी जारी रह सकती है। इसके प्रभाव से तेज धूल भरी आंधी चलने और हल्की बारिश होगी। इससे तापमान में भी कमी आएगी और मौजूदा भीषण गर्मी से भी कुछ राहत मिलेगी।

इस बीच मंगलवार को चुभन भरी धूप के बीच दिल्ली वासियों को खासी गर्मी झेलनी पड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 41.6 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 23 से 71 फीसद रहा। स्पोर्टस काम्प्लेक्स 42.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 29.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ दिल्ली का सर्वाधिक गर्म इलाका रहा।

मौसम में आ रहे बदलाव और फसली अवशेष जलाए जाने की घटनाएं भी लगातार घटने से दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। मंगलवार को भी दिल्ली एनसीआर में कहीं का एयर इंडेक्स रविवार मध्यम तो कहीं का खराब श्रेणी में दर्ज किया गया।

संपादकीय

दूसरी बड़ी लहर से दो-दो हाथ

भारत में कोरोना वायरस महामारी से होने वाली मौतों का आधिकारिक आंकड़ा दो लाख से पार चला गया है। चूंकि यहां सामान्य तौर पर होने वाली मौतों की नियमित जानकारी रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसके लिए लंबी समयावधि की आवश्यकता होती है, ताकि देखा जा सके कि साल में कितनी मौतें सामान्य रूप से होती हैं। ऐसे में, कोरोना से होने वाली मौतों को सटीक ढंग से सामान्य मौतों से अलग कर पाना मुश्किल है। इसका अकेला तरीका यह है कि कुछ अन्य मानकों का सहारा लिया जाए। जैसे फिलहाल चर्चा में बने हुए कुछ मॉडल मौतों की संख्या कम दर्ज कराए जाने को एक हकीकत मानकर चल रहे हैं। इस लिहाज से दो मान्यताओं के आधार पर तय करना अच्छा रहेगा। एक यह कि कोविड-19 में संक्रमण से होने वाली मौतों की दर, यानी संक्रमित हुए लोगों में मरने वालों का अनुपात, और दूसरा है, दर्ज हुए मामलों के साथ न दर्ज कराए गए या पकड़ में ही न आए संक्रमण के मामलों का अनुपात। इनमें दूसरे वाला अनुपात 10, 15 या 20, 25 का भी हो सकता है। और पहला अनुपात वायरल संक्रमणों के बारे में हमारी सामान्य जानकारी के अनुसार, 0.1 प्रतिशत (हाथ रोककर) हो सकता है। यह मैं पाठकों पर छोड़ता हूं कि वे इस गणित को कैसे समझते हैं, क्योंकि यह एक काल्पनिक कसरत है। हालांकि, यह हिन्दुस्तान टाइम्स और अन्य मीडिया समूहों की जमीनी रिपोर्टिंग से भी जाहिर है कि हर राज्य में आधिकारिक रूप से दर्ज की गई मौतों (जो राज्यों के स्वास्थ्य विभागों से मिली जानकारियों के आधार पर हिन्दुस्तान टाइम्स के डैशबोर्ड पर नजर आती हैं) और हर रोज कोविड-19 संक्रमितों के दाह-संस्कार और दफनाने के रूप में जाहिर होने वाली मृत्यु संख्या में भारी अंतर है। संक्रमण अध्ययन के ज्यादातर मॉडल्स का मानना है कि मई के तीसरे हफ्ते तक नए मामलों का बढ़ना रुक जाएगा, लेकिन अभी से इस पर कुछ कहना मुश्किल है। ज्यादातर राज्यों में पॉजिटिविटी रेट (जांच के दौरान पाए गए संक्रमितों का प्रतिशत) उस स्तर पर है, जहां से इसका तेजी से कम होना असंभव प्रतीत होता है (या फिर अगर ऐसा हुआ, तो इससे आंकड़ों की हेराफेरी या कमी का संदेह ही मजबूत होगा), और कुछ राज्यों (मुख्य रूप से महाराष्ट्र) में तो भारत में कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान भी पॉजिटिविटी रेट का ग्राफ तुलनात्मक रूप से बहुत ऊंचा था। इन कुछ जमीनी उदाहरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि देश में कुछ सकारात्मक अनुमानों के बावजूद आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों और उससे होने वाली मौतों का बढ़ना जारी रह सकता है।

हमें इनकी उपलब्धता और समय के बारे में जानकारी की सख्त आवश्यकता है। और हमें वैक्सीन की व्यवस्था को लेकर ऐसीनिश्चित रणनीति बनानी होगी कि इसकी पूर्ण या दोनों खुराक के बजाय पहली खुराक को प्राथमिकता दी जाए, ताकि इस महामारी से ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। (खासकर कोविशील्ड वैक्सीन, जो 90 प्रतिशत लोगों को दी गई है)। अगर अगले छह हफ्तों तक ऐसा संभव हो पाए, तो भारत इस दूसरी लहर को तोड़ सकता है और तीसरी के लिए खुद को तैयार कर सकता है।

आम बातचीत से पता चलता है कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी के कारण भी कुछ मौतें हुई हैं, और ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में अधिक संख्या में संक्रमण के मामले सामने आने से हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहुत भार पड़ गया है। इसका यह भी मतलब है कि एक बार अगर कोविड रोगियों की सेवा में जुटे अस्पतालों में चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और वितरण सुचारु हो जाए (जिसके प्रयास शुरू हो गए हैं और सप्ताह के अंत तक इसके पूरा होने के संकेत हैं), तो मौतों की संख्या भी घटनी शुरू हो जाएगी। हम साफ देख रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने में ऑक्सीजन की कमी एक प्रमुख अड़चन के रूप में हमारे सामने आई है- और यहां यह याद रखना जरूरी है कि देश को कोरोना की तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना है, जिसका किसी न किसी बिन्दु पर उभरना तय है। कोरोना के टीके भी संक्रमण की दूसरी लहर को तोड़ने और तीसरी लहर की प्रचंडता को कम करने में बहुत मददगार हुए हैं, लेकिन इन टीकों की आपूर्ति और लोगों तक उपलब्धता के बारे में बहुत कम जानकारी है। भारतीय बाजार में उपलब्ध कोरोना के टीकों की खुराक को लेकर स्पष्टता नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी खरीदारों के स्तर पर भी स्थिति साफ नहीं है। भारत की दो बड़ी घरेलू वैक्सीन उत्पादक कंपनियों, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की निर्यात संबंधी संविदाओं के बाद देश में इनकी आपूर्ति किस तरह या कितनी होगी, ठीक से कहा नहीं जा सकता। इस बारे में भी कोई स्पष्टता नहीं है कि रूस निर्मित वैक्सीन स्पुतनिक वी की कितनी खुराक भारत में उपलब्ध होगी लोगों के बीच जो भी सीमित जानकारी उपलब्ध है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत को जितने कोरोना टीकों आवश्यकता है, उतने की आपूर्ति संभव नहीं हो पाएगी। अब जबकि मई की पहली तारीख से भारत में टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने वाला है, तब भी यह पता नहीं चल पा रहा है कि जिन राज्यों ने वैक्सीन के लिए ऑर्डर दिए हैं, उन्हें वैक्सीन की खुराक कब तक मिल पाएगी। हमें इनकी उपलब्धता और समय के बारे में जानकारी की सख्त आवश्यकता है। और हमें वैक्सीन की व्यवस्था को लेकर ऐसीनिश्चित रणनीति बनानी होगी कि इसकी पूर्ण या दोनों खुराक के बजाय पहली खुराक को प्राथमिकता दी जाए, ताकि इस महामारी से ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। (खासकर कोविशील्ड वैक्सीन, जो 90 प्रतिशत लोगों को दी गई है)। अगर अगले छह हफ्तों तक ऐसा संभव हो पाए, तो भारत इस दूसरी लहर को तोड़ सकता है और तीसरी के लिए खुद को तैयार कर सकता है।

प्रवीण कुमार सिंह

सरकार के साथ समाज का सहकार भी जरूरी, तभी तो दूर होगा कोरोना संकट

समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना चाहिए। समाज और राज का सम्मिलित प्रयास जरूरी है। राजनीतिक दल तंत्र को भी मिलकर काम करना चाहिए। समाज का बड़ा भाग भयग्रस्त है। भय से अवसाद बढ़ता है। अवसाद से रोग निरोधक शक्ति का ह्रास होता है। आम जनमानस के मध्य आशावाद और कर्तव्यपालन का भाव बढ़ाना जरूरी है। ऋग्वेद के अंतिम सूक्त में स्तुति है, 'हम सब साथ-साथ चलें, साथ-साथ संवाद करें, ऐसे ही पूर्वकाल में हमारे पूर्वज भी करते रहे हैं।' महामारी स्थाई नहीं है। यह भी एक दिन जाएगी ही। शर्त है कि हम अपना कर्तव्यपालन करें और मित्रों से भी ऐसा ही आग्रह करें।

देश-दुनिया कोरोना महामारी से भयग्रस्त है। भय कल्पित अशुभ का मनोशरीरी प्रभाव है। जो नहीं हुआ है, उसकी कल्पना या आशंका है भय। भय इसी आशंका का बुरा मानसिक प्रभाव है। महामारी से जूझने के लिए राष्ट्रराज्य ने सारे संसाधन झोंक दिए हैं। प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार परामर्श कर रहे हैं। सरकारी तंत्र एवं प्रशासन भी सक्रिय हैं। हजारों मरीज ठीक हो रहे हैं। टीकाकरण भी जारी है। ऑक्सीजन आपूर्ति के मोर्चे पर युद्ध स्तरीय प्रयास हैं। कोरोना की पराजय निश्चित है। कोरोना की पहली लहर के समय सैकड़ों सामाजिक संस्थाएं भी स्वत:स्फूर्त सक्रिय थीं। वे भोजन पैकेट सहित सभी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति कर रही थीं। औद्योगिक संस्थान भी सहायतार्थ सक्रिय थे। राज और समाज मिलकर लड़ रहे थे। दूसरी लहर ज्यादा प्राणलेवा है। इसलिए सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। सामाजिक संस्थाओं को और आगे आना चाहिए। सरकार के साथ समाज का सहकार भी जरूरी है। संप्रति प्रत्येक स्तर पर समन्वय की जरूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त भय इसी से दूर होगा।

महामारियों का प्रकोप हजारों वर्ष प्राचीन है। यूरोपीय देशों में भी महामारी के प्रकोप रहे हैं। प्लेग भयंकर महामारी थी। इसकी शुरुआत 14वीं सदी में हुई। दि कैंब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ यूरोप (खंड-चार) के अनुसार, 'इसके बाद लगभग 350 साल तक इसने हजारों की जान ली। महामारी प्राय: महानगरों से फैलती थी।' कोरोना भी महानगरों से ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहा है। 18वीं सदी के अंत में बंगाल में प्लेग का भयंकर प्रकोप था। लोग भयग्रस्त थे। स्वामी विवेकानंद ने प्लेग मेनीफेस्टो जारी किया। यह बांग्ला और हिंदी में भी था। भगिनी निवेदिता और स्वामी सदानंद सहित तमाम महानुभावों ने इसका वितरण कराया। भय को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा थी, 'सब भय मुक्त

रहें। भय सबसे बड़ा पाप है।' विवेकानंद ने तब कहा था, 'मस्तिष्क को आनंद से भरापूरा रखें। सबकी मृत्यु निश्चित है। कायर मृत्यु भय से बार-बार मरते हैं। उनके मस्तिष्क में भय रहता है।' उन्होंने भयमुक्ति पर जोर देते हुए कहा, 'आइए! हम सब झूठा भय त्याग दें। कर्म क्षेत्र में जुटें। उन्होंने स्वच्छता की बात भी की, घर, वस्त्र, स्वच्छ रखें और शुद्ध भोजन रहन-सहन भी। अफवाहें न फैलें।' ये सारी बातें कोरोना प्रोटोकॉल से भी संबंधित दिखती हैं। हालांकि उनके कथन सवा सौ साल पुराने हैं। तब आज जैसा चिकित्सा तंत्र नहीं था और न ही साधन संपन्नता। मूलभूत प्रश्न है कि 125 वर्ष पहले विवेकानंद ने महामारी से टकराने के जो स्वर्ण सूत्र बताए थे, आज हम साधन संपन्न होकर भी वैसे ही सूत्र क्यों नहीं अपना सकते?

प्रकृति में जीवन के भरण-पोषण की व्यवस्था है। प्राकृतिक जीवन में प्राण ऊर्जा का घनत्व ज्यादा होता है। मनुष्य ने प्रकृति का दोहन-शोषण किया। जल, वायु और आकाश तक घायल हैं। वनस्पतियों का विनाश हुआ। महानगरों तक तत्काल पहुंचने के लिए हवाई जहाज। हिंसा के लिए परमाणु हथियार। सभ्यता का आधुनिक स्वभाव ही प्रकृति विरोधी है। मनुष्य और प्रकृति के मध्य अंतर्विरोध बढ़े। मनुष्य ने ही महामारियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया। ज्ञात इतिहास में एथेंस में युद्ध के समय पहली महामारी प्रकट (430 ईपू) हुई। यह लीबिया, इथोपिया और मिस्र तक पहुंची। फिर प्लेग आया। इसने जर्मन, रोमन पर हमला किया। ब्रिटेन भी इसका निशाना बना। प्लेग ने 1665 में लंदन की 20 प्रतिशत आबादी का नाश किया। 1817 में कालरा से रूस में हजारों मरे। स्पेन, अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन, जापान, इटली में भी हजारों लोग मृत्यु का शिकार हुए। दुनिया में महामारियों से लाखों मौतें हुई हैं।

इधर चिकित्सा विज्ञान ने बहुत उन्नति की है। तमाम मारक बीमारियों के वैक्सीन बन गए हैं, लेकिन वायरस पैंतरा बदल कर नई क्षमता के साथ सामने है। कोरोना संकट भयावह है। लोग मर रहे हैं, लेकिन समाज के बड़े हिस्से द्वारा दो गज की दूरी और मास्क लगाने की प्रार्थना की अवहेलना भी हो रही है। आखिरकार हम कैसे सभ्य देश हैं? प्रधानमंत्री ने पहले चरण में ही हाथ जोड़कर समस्या से निपटने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को खतरा था। लॉकडाउन का एक सीधा संबंध मास्क लगाने और दो गज की भौतिक दूरी के अनुपालन से है। लोग यह बात मानने को तैयार नहीं हैं। उप्र की योगी सरकार समेत अन्य कई राज्य सरकारों ने इसी अनुपालन के लिए प्रति शनिवार-रविवार की बंदी की घोषणा की है। मास्क और भौतिक दूरी ही इस महामारी के बचाव हैं, लेकिन आखिर मास्क न लगाने और भौतिक दूरी का अनुपालन न करने वाले लोगों को कौन समझाए?

महामारी लाखों को निगलती है। भारत में कम से कम चार महामारियों का इतिहास त्रासद है। 1974 में चेचक से हजारों मौतें हुईं, फिर इसका टीका आया। 1994 के प्लेग में हजारों लोग मारे गए। 1918 में भयावह फ्लू से भी लाखों लोगों की मौतें हुईं।

कहते हैं कि महात्मा गांधी भी संक्रमण के शिकार हुए थे। स्वाधीनता आंदोलन में भी इसका प्रभाव पड़ा। सैनिटरी कमीशन की रिपोर्ट (1918) में कहा गया कि भारत की सभी नदियों में शव थे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी लिखा था कि गंगा में मृतकों के शव उतरा रहे थे। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी का अभाव था। तब देश का चिकित्सा तंत्र कमजोर था। अंग्रेजी राज था। वे भारत के प्रति असंवेदनशील थे। अब ऐसा नहीं है।

सरकारें चिकित्सा तंत्र को लगातार विस्तार दे रही हैं। सरकारें अति व्यस्त हैं। वे लोगों को जागरूक करने के लिए समाचार माध्यमों पर निर्भर हैं। गैर सरकारी संगठनों और सरकारी प्रतिनिधियों के मध्य समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना चाहिए। समाज और राज का सम्मिलित प्रयास जरूरी है। राजनीतिक दल तंत्र को भी मिलकर काम करना चाहिए। समाज का बड़ा भाग भयग्रस्त है। भय से अवसाद बढ़ता है। अवसाद से रोग निरोधक शक्ति का ह्रास होता है। आम जनमानस के मध्य आशावाद और कर्तव्यपालन का भाव बढ़ाना जरूरी है। ऋग्वेद के अंतिम सूक्त में स्तुति है, 'हम सब साथ-साथ चलें, साथ-साथ संवाद करें, ऐसे ही पूर्वकाल में हमारे पूर्वज भी करते रहे हैं।' महामारी स्थाई नहीं है। यह भी एक दिन जाएगी ही। शर्त है कि हम अपना कर्तव्यपालन करें और मित्रों से भी ऐसा ही आग्रह करें।

कोविड महामारी चिकित्सकीय शोध, नवाचार को बढ़ावा देने का एक अवसर

निस्संदेह अभी स्वास्थ्य मोर्चे पर आपातकाल जैसी स्थिति है, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि कोरोना महामारी के दौरान भारत ने दवाइयों के उत्पादन और निर्यात में असाधारण भूमिका निभाई है। भारत आज पीपीई किट, वेंटीलेटर, सर्जिकल मास्क, मेडिकल गॉगल्स आदि का बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बन गया है। इस समय दवाई उत्पादन की मात्रा के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत में दवाई उत्पादन की लागत अमेरिका एवं पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत कम है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में जहां वैश्विक दवा बाजार में करीब दो फीसद की गिरावट आई, वहीं भारत का दवा निर्यात 18 फीसद बढ़कर करीब 24.44 अरब डॉलर यानी करीब 1.76 लाख करोड़ रुपये की ऊंचाई पर पहुंच गया है। भारत से दवा निर्यात न केवल विकासशील देशों, वरन यूरोपीय देशों और अमेरिका सहित कई विकसित देशों में भी बढ़ा है।

भारत कोरोना वैक्सीन निर्माण के नए मुकाम की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस समय दुनियाभर में इस्तेमाल की जाने वाली करीब 60 फीसद वैक्सीन भारत में बनाई जाती हैं। ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाई गई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड तथा स्वदेश में विकसित भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का उपयोग देशव्यापी टीकाकरण अभियान में किया जा रहा है। भारत अब तक 80 से अधिक देशों को छह करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की खुराक दे चुका है। भारत कोरोना वैक्सीन का भी वैश्विक स्तर पर बड़ा आपूर्तिकर्ता बनने की तैयारी कर रहा है। इस दिशा में नीतिगत स्तर पर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कई अहम फैसले लिए गए हैं। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में सूचीबद्ध कोरोना वैक्सीन के स्वदेश आने का रास्ता साफ कर दिया है। इससे विदेशी वैक्सीन का तत्काल आयात किया जा सकेगा।

वैक्सीन उत्पादन से जुड़े कच्चे माल का आयात करके बड़ी मात्रा में कोरोना वैक्सीन का निर्यात भी किया जा सकेगा। इसके अलावा अब शीघ्र ही विदेशी कंपनियां भारत में अपनी सहयोगी कंपनी या फिर अपने अधिकृत एजेंट के माध्यम से वैक्सीन का उत्पादन कर सकेंगी। हैदराबाद की प्रमुख दवा कंपनी डॉ. रेड्डी लैब. कोविड-19 के लिए रूस में तैयार टीका स्पुतनिक वी के लिए भारतीय साझीदार है। इसके द्वारा स्पुतनिक टीके का 60 से 70 फीसद वैश्विक उत्पादन भारत में होगा। इतना ही नहीं क्वॉड के चार देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत द्वारा भारत में वर्ष 2022 के अंत तक कोरोना वैक्सीन की सौ करोड़ डोज बनाने का जो निर्णय लिया गया है, उससे भारत दुनिया की कोरोना वैक्सीन महाशक्ति के रूप में उभरेगा।

यह भी महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश को दवा निर्माण का गढ़ बनाने के मद्देनजर अधिक कीमतों वाली दवाइयों के स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन देने और चीन से बाहर निकलती फार्मा कंपनियों को देश में आकर्षित करने के उद्देश्य से फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए 15,000 करोड़ रुपये की पीएलआइ योजना बनाई है। इससे देसी-विदेशी दवा कंपनियों से करीब 50,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है।

पीएलआइ स्कीम के तहत सरकार द्वारा दवा बनाने के लिए कच्चे माल के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 6940 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन धनराशि भी घोषित की गई है। इससे दवाओं के पूरक पदार्थों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इससे जहां दवा क्षेत्र की बिक्री बढ़कर करीब तीन लाख करोड़ रुपये हो जाएगी, वहीं दवा निर्यात में भी करीब दो लाख करोड़ रुपये का इजाफा होगा। फार्मेसी सेक्टर की प्रमुख कंपनियां ल्युपिन, डॉ. रेड्डीज, सिप्ला और कैडिला हेल्थकेयर आदि पीएलआइ योजना के तहत निवेश करने का मंतव्य बना चुकी हैं।

स्पष्ट है कि कोविड-19 भारत में नए चिकित्सकीय शोध और नवाचार को बढ़ावा देने का भी एक अवसर बन गया है। सामान्य तौर पर किसी बीमारी का टीका बनाने में कई वर्ष लगते हैं, लेकिन भारत में कोरोना वायरस की चुनौती के मद्देनजर कुछ महीनों के अंदर कोरोना टीका बनाने का कठिन लक्ष्य पूरा करके बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक उत्पादन किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के बजट में शोध एवं नवाचार के लिए 50 हजार करोड़ रुपये खर्च किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन का एलान भी किया गया है, जो इसी साल से काम शुरू कर देगा। साथ ही विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत चार पायदान ऊपर चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंच गया है।

दुनिया के मानचित्र पर भारत के वैश्विक फार्मेसी और कोरोना वैक्सीन का हब बनने की जो संभावनाएं बनी हैं, उन्हें भुनाने के हरसंभव प्रयास करने होंगे। इससे आगामी पांच वर्षों में भारत का फार्मा सेक्टर मौजूदा करीब 40 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 तक 65 अरब डॉलर और 2030 तक 120 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच जाएगा। इसके लिए फार्मा सेक्टर से संबंधित पीएलआइ योजना से दवा उत्पादन बढ़ाने पर सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। फार्मा सेक्टर में शोध-अनुसंधान पर खर्च बढ़ाना होगा।

हम होंगे कामयाब

कोरोना की दूसरी लहर के बीच अमेरिकी मदद की पहली खेप शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गई। भारत इन दिनों जिस तरह के हालात से जूझ रहा है, उसे देखते हुए दुनिया के तमाम देश मदद के लिए आगे आए हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, साउथ कोरिया, सिंगापुर समेत 40 से अधिक देशों की ओर से सहायता सामग्री या तो देश में पहुंच चुकी है या पहुंचने की प्रक्रिया में है। अमेरिका ने जरूरी दवाएं, एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफर्ड की वैक्सीन यानी कोविशील्ड और इसे बनाने के लिए कच्चा माल भी भिजवाया है।

यों तो भारत की मदद का फैसला लेने में अमेरिकी प्रशासन की शुरुआती हिचक से कुछ सवाल खड़े होने लगे थे, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सही समय पर सटीक फैसला करके उन्हें जड़ें जमाने का मौका नहीं दिया। जिन देशों ने भारत की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है, उनसे सरकार ने मेडिकल ऑक्सिजन, रेमडेसेवियर जैसी दवाएं मांगी हैं ताकि कोविड से गंभीर रूप से बीमार लोगों का इलाज किया जा सके। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने बताया है कि इन देशों को हमने अपनी जरूरतें बता दी हैं। इस बारे में उच्चस्तर पर बातचीत चल रही है। महामारी से जंग में सरकारों के साथ कई देशों के आम लोग भी भारतीयों का हौसला बढ़ा रहे हैं।वे इसके लिए सोशल मीडिया पर संदेश दे रहे हैं और अपनी सरकारों से हर संभव तरीके से भारत की मदद करने का आग्रह कर रहे हैं। भारत ने भी %वैक्सीन मैत्री% के तहत नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस जैसे देशों को न सिर्फ टीके की सप्लाई की बल्कि वह डब्ल्यूएचओ की कोवैक्स इनीशिएटिव में भी योगदान कर रहा है। कोवैक्स नाम की पहल खासतौर पर वैसे विकासशील और गरीब देशों को वैक्सीन दिलाने के लिए शुरू की गई है, जिनके पास अपना टीका नहीं है। इसलिए आज दुनिया भर से भारतीयों की मदद के लिए जो हाथ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कुछ भूमिका निश्चित रूप से भारत के उन कार्यों से बने सद्भाव की भी है।

इस मुश्किल घड़ी में जिस तरह से कई देश मदद के लिए आगे आए हैं, उससे पता चलता है कि दुनिया भले अलग-अलग देशों की सरहदों में बंटी हो, लेकिन इंसानियत का धागा सबको इतनी मजबूती से जोड़ता है कि किसी भी संकट की घड़ी में सारी सरहदें छोटी पड़ जाती हैं। इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है। जब तक दुनिया में कहीं भी इससे लोग पीड़ित रहेंगे, तब तक हम इसके खिलाफ जंग नहीं जीत पाएंगे। इसलिए हमें इससे मिलकर लड़ना होगा। तभी हम सदी में एक बार आने वाली ऐसी आपदा को हरा पाएंगे।

बंगाल वह धुरी है जिस पर हमारी 'एक्ट ईस्ट' नीति की सफलता निर्भर करती है

बंगाल वह धुरी है जिस पर हमारी 'एक्ट ईस्ट' (पूरब के देशों की ओर उन्मुख) नीति की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के प्रवेश द्वार की हैसियत रखता है। प्रधानमंत्री ने मैन्युफैक्चरिंग में बंगाल के ऐतिहासिक प्रभुत्व को बहाल करने की अपनी ख्वाहिश के बारे में बात की थी। केंद्र ने अपना काम पूरा किया और देश के बंटवारे के समय के रास्तों को फिर से चालू करने तथा उत्तर पूर्व को रास्ता देने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर खोलने के लिए बांग्लादेश के साथ साझेदारी की दिशा में कदम बढ़ाया है। बंगाल के नेताओं ने दशकों से उधार के वैभव पर गर्व की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। यह बंगाल के पुराने वैभव को वापस पाने और इसकी खोई मानव संपदा को वापस लाने का समय है।

वर्ष 1950 में भारत की औद्योगिक पूंजी का करीब 25 फीसद हिस्सा बंगाल में था। यह 1960 तक घटकर 13 फीसद और फिर 2000 तक लगभग सात फीसद पर आ गया। एक समय बंगाल एक आर्थिक महाशक्ति और भारत का अग्रणी वित्तीय केंद्र था। आजादी के बाद के वर्षों में वह अथाह दौलत से लबरेज था और जैसा कि इतिहासकार विलियम डैलरिंपल अपनी किताब द एनार्की में लिखते हैं, 'यहां के जगत सेठ द्वारा मुहैया कराए गए धन की मदद के बिना औपनिवेशिक शासन संभव नहीं होता।' आजादी के बाद भी बंगाल विकास पथ पर आगे बढ़ता रहा। 1948 और 1965 के बीच की अवधि को ऐसे दौर के रूप में याद किया जाता है, जब यहां नए उद्योग (जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट, दामोदर वैली कॉरपोरेशन पावर स्टेशन) लगाए गए। इसके चलते 1947-1958 के बीच उसकी सालाना विकास दर 3.31 फीसद रही, जो समूचे भारत से ज्यादा थी।

1950-59 के मध्य तक बंगाल की देश के औद्योगिक उत्पादन में 24 फीसद और राष्ट्रीय रोजगार में 27 फीसद हिस्सेदारी थी। 1965 तक बंगाल 20 फीसद औद्योगिक उत्पादन में हिस्सेदारी के साथ अपनी दमदार स्थिति बनाए हुए था। राज्य विकास की उड़ान भरने के लिए तैयार था। तभी वामपंथी सत्ता में आए। वामपंथियों ने 1967 के बाद राज्य में औद्योगीकरण की बर्बादी में बड़ी भूमिका निभाई। 1970-71 तक औद्योगिक उत्पादन में बंगाल की हिस्सेदारी घटकर 13.5 फीसद रह गई, जबकि महाराष्ट्र (गुजरात को छोड़कर) की

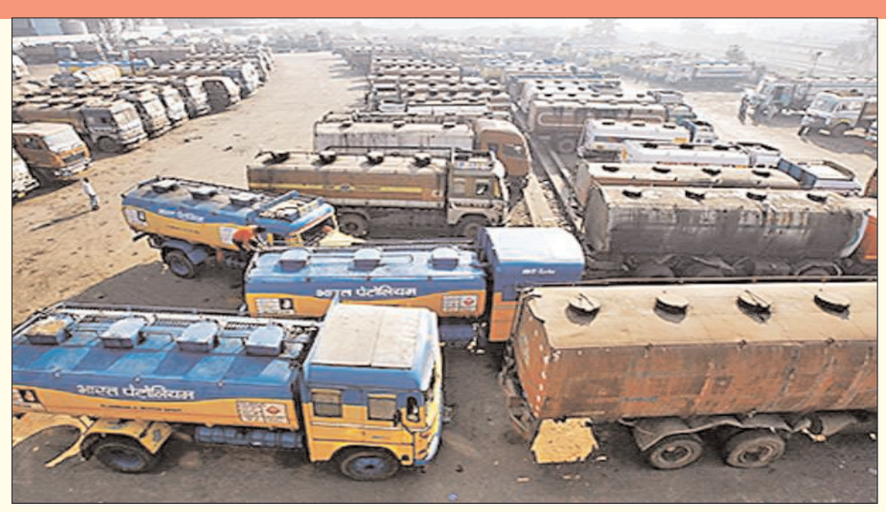

बढ़कर लगभग 25 फीसद पर पहुंच गई। ट्रेड यूनियनों के उत्पात ने गहरी चोट पहुंचाई।

बंगाल में 1965 और 1970 के बीच हड़तालों की संख्या 179 से बढ़कर 678 (3.8 गुना) हो गई, जबकि फैक्ट्रियों में तालाबंदी की घटनाएं 49 से बढ़कर 128 (2.6 गुना) हो गईं। फसलें चौपट होने के चलते अन्न के लिए दंगे हुए और आखिरकार नक्सलवाद का जन्म हुआ। ऐसे हालात ने बंगाल की पूंजी और प्रतिभा के पश्चिमी भारत की ओर पलायन को बल दिया, लेकिन आगे और बुरा दौर आना बाकी था। हालांकि 1990 तक बंगाल को अच्छे बुनियादी ढांचे के लिए जाना जाता था, लेकिन उसमें भी गिरावट आई, क्योंकि वहां छंटनी आम चलन बन गया।

एक रिपोर्ट बताती है कि राज्य ने कारखानों की 1,77,000 नौकरियां गंवा दी। यही वह दौर था जब निवेशक बंगाल से छिटक कर दूर चले गए और साथ ही कृषि क्षेत्र में भी गिरावट आई। इस तरह बंगाल बर्बाद हो गया। इस बदहाली को ठीक करने के लिए किए गए नेतृत्व में बदलाव से भी कुछ खास नहीं बदला। राष्ट्रीय आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण 2017-18 की रिपोर्ट के मुताबिक बीते एक दशक में तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में बेरोजगारी बढ़ी है। बुनियादी तौर पर बंगाली कामगारों को सामाजिक सुरक्षा हासिल नहीं है। राज्य भारी कर्ज और संसाधनों का सही इस्तेमाल कर पाने में अक्षमता के बोझ तले दबता जा रहा है। सुधार की फौरन जरूरत है।

बंगाल के पुनरुद्धार की कुंजी इन बिंदुओं पर आधारित है? कोलकाता में फिर से निवेश लाना और आसनसोल से हल्दिया तक मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट को दोबारा सक्रिय करना। एक समय कोलकाता वर्ल्ड सिटी था, जो न्यूयॉर्क और पेरिस से बराबरी करता था, फिर इस पर बदकिस्मती का साया पड़ा और एक सदी पहले इसने भारत की राजधानी का दर्जा गंवा दिया। स्वेज नहर बनने के बाद इसका आर्थिक वर्चस्व छिन गया। वामपंथियों के हाथों तबाह किए जाने के बाद शहर गरीब भारत की परंपरागत तस्वीर बन कर रह गया।

आज कोलकाता में दुनिया के देशों के लिए 'बैक-ऑफिस' के तौर पर काम करने के लिए काफी संभावनाएं हैं। इस शहर में जबरदस्त पर्यटन क्षमता भी है। औपनिवेशिक काल की वास्तुकला, संस्कृति, नाइट-लाइफ और सुरक्षा का ऐसा जबरदस्त मिश्रण किसी भी दूसरे भारतीय शहर में नहीं है। शहर को एशिया के हवाना के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म सेक्टर को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की जरूरत है। कुल मिलाकर कोलकाता को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में बहाल करना प्राथमिकता होनी चाहिए।

आज बंगाल को मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निजी निवेश के लिए सुरक्षित माहौल मुहैया कराने की जरूरत है, जिसके साथ अच्छी सड़कें और रेल का बुनियादी ढांचा हो। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से बिहार को जाने वाले नए एक्सप्रेस-वे को बंगाल के औद्योगिक केंद्रों से जोड़ना चाहिए। ऐसी ही कनेक्टिविटी ब्रह्मपुत्र घाटी से दी जानी चाहिए। कानून-व्यवस्था भी एक बड़ी समस्या है। किसी औद्योगिक संस्थान के लिए धरना-घेराव भविष्य के किसी भी निवेश में रुकावट होगा। कानून का शासन बड़ा फर्क ला सकता है। इसके अलावा पीएलआइ (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) स्कीम के तहत बंगाल में चुनिंदा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए तैयार की गई स्कीमें निर्यात को बढ़ा सकती हैं।

बंगाल वह धुरी है जिस पर हमारी 'एक्ट ईस्ट' (पूरब के देशों की ओर उन्मुख) नीति की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के प्रवेश द्वार की हैसियत रखता है। प्रधानमंत्री ने मैन्युफैक्चरिंग में बंगाल के ऐतिहासिक प्रभुत्व को बहाल करने की अपनी ख्वाहिश के बारे में बात की थी। केंद्र ने अपना काम पूरा किया और देश के बंटवारे के समय के रास्तों को फिर से चालू करने तथा उत्तर पूर्व को रास्ता देने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर खोलने के लिए बांग्लादेश के साथ साझेदारी की दिशा में कदम बढ़ाया है। बंगाल के नेताओं ने दशकों से उधार के वैभव पर गर्व की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। यह बंगाल के पुराने वैभव को वापस पाने और इसकी खोई मानव संपदा को वापस लाने का समय है। इस सबके लिए सिर्फ एक सही नेतृत्व की जरूरत है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

कोरोना की घेराबंदी के लिए यूपी के गांवों में विशेष अभियान, दस लाख एंटीजेन जांच का लक्ष्य

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव निपट गए हैं। तेज गति से गांवों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की आशंकाएं सिर उठा रही हैं। इससे पूरी तरह सतर्क योगी आदित्यनाथ सरकार ने गांवों में कोरोना की घेराबंदी के लिए व्यूह रचना कर ली है। बुधवार से प्रदेश के सभी राजस्व गांवों में पांच दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें घर-घर दस्तक देकर लक्षण वाले मरीजों की जांच की जाएगी।

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने तेजी से उत्तर प्रदेश को अपनी चपेट में लिया है। तमाम शहरों में स्थिति काफी खराब है। सरकार इसकी रोकथाम के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके साथ ही अब गांवों के बचाव के लिए विशेष अभियान चलाने का फैसला सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि बुधवार से पांच दिवसीय अभियान शुरू किया जाए।

अपर मुख्य सचिव सूचना डॉ. नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश के सभी 97 हजार राजस्व गांवों में निगरानी समितियां और रैपिड रेस्पांस टीमें घर-घर दस्तक देंगी। निगरानी समितियों को दस लाख मेडिसिन किट, जबकि रैपिड रेस्पांस

टीमों को दस लाख एंटीजेन टेस्ट किट दी गई हैं। कुल दस लाख जांचों का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि टीमें पल्स आक्सीमीटर व अन्य जांचों से पता करेंगी कि किसी को कोरोना संक्रमण के लक्षण तो नहीं है। लक्षण मिलने पर मेडिसिन किट दी जाएगी। आइसोलेट कराया जाएगा। यदि जरूरत हुई तो मरीज को अस्पताल में भी भर्ती कराया जाएगा।

बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान ही होली का त्योहार बीता। तब तमाम प्रवासी अपने गांव-गांव पहुंचे। गेहूं की कटाई के बाहर से भी मजदूर गांवों में पहुंचे। इसी तरह पंचायत चुनावों ने भी संक्रमण फैलने की आशंका पैदा कर दी। माना जा रहा है कि सावधानी बरतते हुए ही सरकार ने विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। मरीजों को आइसोलेट करने में भी समस्या नहीं आएगी। यदि किसी ग्रामीण के घर में व्यवस्था नहीं होगी तो सरकार पहले ही हर गांव में क्वारंटाइन सेंटर बनाने के निर्देश दे चुकी है।

होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए अलग ऑक्सीजन रीफिलर : होम आइसोलेशन के मरीजों को ऑक्सीजन आपूर्ति की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों में एक-एक ऑक्सीजन रीफिलर को होम आइसोलेशन के मरीजों को आपूर्ति करने के लिए नामित किया जाए। होम आइसोलेशन में उपचाराधीन लोगों को जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन जरूर मिले। यदि किसी मरीज के परिजन सिलिंडर रीफिलिंग के लिए प्रयासरत हों तो उनकी मदद की जाए। पुलिस द्वारा किसी प्रकार के उत्पीड़न की शिकायत न आए।

किसी मजदूर को न हो भोजन की समस्या : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के कारण कहीं भी किसी श्रमिक, ठेला, रेहड़ी व्यवसायी, दैनिक मजदूर आदि को भोजन की समस्या न हो। ऐसे में सामुदायिक भोजनालय चलाने की जरूरत है। कृषि उत्पादन आयुक्त स्तर से यह व्यवस्था बनाई जाए। औद्योगिक इकाइयों में भी भोजन आदि का प्रबंध रहे।

डॉक्टर की मौजूदगी में लगे रेमडेसिविर : भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का दैनिक आवंटन बढ़ा दिया है। सरकारी कोविड अस्पतालों में यह इंजेक्शन निशुल्क दिया जा रहा है। व्यवस्था है कि निजी अस्पतालों को जरूरत के अनुसार डीएम-सीएमओ द्वारा इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम योगी ने कहा है कि सभी जिलाधिकारी और सीएमओ यह सुनिश्चित करें कि जब भी किसी मरीज को यह इंजेक्शन दिया जाए तो वहां नर्सिंग स्टाफ के साथ-साथ एक डाक्टर भी उपस्थित हो। इस जीवनरक्षक दवा की मांग, आपूर्ति और खपत का पूरा विवरण रखा जाए।

यूपी में 10 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, अब चार दिन और रहेगा कोरोना कर्फ्यू

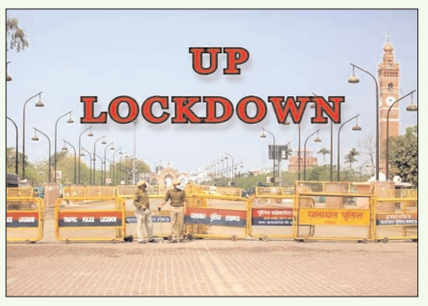

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार सख्ती बढ़ा रही है। दो दिन की साप्ताहिक बंदी को तीन दिन करने के बाद अब फिर चार दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले साप्ताहिक बंदी तीन मई और फिर छह मई तक थी। अब इसे बढ़ाकर सोमवार यानी 10 मई सुबह सात बजे तक के लिए कर दिया है। सरकार के फैसले के अनुसार लॉकडाउन को चार दिन और बढ़ा दिया गया है। इस दौरान पूर्ण रूप से बंदी रहेगी, लेकिन जरूरी चीजों की दुकानें व जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी।

कोरोना संक्रमण को बढ़ते देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चिंता जता रहे हैं। कोविड का वर्तमान स्ट्रेन लगातार रूप बदल रहा है। यह पहली लहर की तुलना में 30 से 50 गुना अधिक संक्रामक है। बेकाबू कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार अब धीरे-धीरे सख्ती बढ़ाती नजर आ रही है। दो दिन की साप्ताहिक बंदी को तीन दिन करने के बाद अब सरकार ने इसे 10 मई सुबह सात बजे तक के लिए कर दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 के साथ हुई बैठक में कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार लगातार जरूरी कदम उठा रही है। प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी प्रभावी है। इसे और विस्तार दिया जा रहा है। अब प्रदेश में सोमवार सुबह सात बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इस अवधि में आवश्यक और अनिवार्य सेवाएं जारी रहेंगी। दवा, सब्जी की दुकानें, औद्योगिक इकाइयां आदि चलती रहेंगी।

गांवों में घर-घर जा रही कोरोना जांच टीम - ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार से घर-घर जांच अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान नौ मई तक चलेगा। इस दौरान गांव के हर व्यक्ति के बारे में जानकारी ली जाएगी, जिन लोगों में कोरोना के लक्षण होंगे अथवा जो दूसरे प्रदेश से लौट कर आए हैं उनकी कोविड जांच की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं।

हर टीम को 1000 लोगों की जिम्मेदारी दी गई है। यह टीम गांव में जाएगी। लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेगी। परिवार में किसी को बुखार होगा तो उसे मेडिकल किट उपलब्ध कराएगी।

कोविड की रोकथाम के लिए राज्य सलाहकार समिति गठित - कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम और उपचार के लिए शासन को समय-समय पर आवश्यक परामर्श देने के लिए राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस बारे में मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। राजधानी के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के निवेशक डॉ. आरके धीमन की अध्यक्षता में गठित इस समिति के सदस्य किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटीके कुलपति डॉ. ले. जनरल विपिन पुरी, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति डॉ. एके सिंह, डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की निदेशक डॉ. सोनिया नित्यानंद, मेदांता हॉस्पिटल के डॉ. राकेश कपूर, एसजीपीजीआइ के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रो. आरके सिंह, एसजीपीजीआइ के डॉ. आलोक नाथ, केजीएमयू के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के डॉ. वेद प्रकाश, सुपर स्पेशियल्टी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा के निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता, लखनऊ के मिडलैंड हॉस्पिटल के डॉ. बीपी सिंह, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के निदेशक, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, स्टेट सर्विलांस ऑफिसर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण होंगे।

संक्षिप्त खबर

प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा - टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी लोकतंत्र के नाम पर कलंक

लखनऊ । पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हिंसा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी बुधवार को पूरे प्रदेश में धरना दें रहे हैं। मंडल व बूथ स्तर पर कोविड प्रोटोकाल व लाकडाउन का ध्यान रखते हुए भाजपाई अपने- अपने घरों पर विरोध जता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह भी अपने आवास पर धरने पर बैठे हैं। सभी पार्टी पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से धरना देने को कहा गया है।

प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी में जहां मानव एक दूसरे की जान बचाने के लिए प्रयासरत है, वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के संरक्षण में लगातार हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही हैं। भाजपाइयों के घरों व प्रतिष्ठानों तथा पार्टी कार्यालयों को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी लोकतंत्र के नाम पर कलंक है। जिसके विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशानुसार करीब एक घंटे के धरने के दौरान कार्यकर्ताओं की संख्या एक बार में 20 से अधिक नहीं होगी।

सेवा कार्य प्रभावित न हों - प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश, क्षेत्र, जिला व मंडल पदाधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि अपने-अपने घरों पर ममता सरकार के संरक्षण में हो रही हिंसा के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करेंगे। उन्होंने आगाह किया कि सेवा ही संगठन अभियान-2 के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड पीड़ितों के लिए किए जा रहे सेवा कार्य इस धरने से प्रभावित न हों, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

बीटीआर में बारिश से लौटी हरियाली, जानवरों को पानी के लिए नहीं होगी परेशानी

पश्चिम चंपारण । बीते दिनों हुई बारिश से वीटीआर के जंगल फिर से हरे-भरे हो गए हैं। जिससे भीषण गर्मी में फिर से हरियाली लौट आई है। जंगल में घास भी उग गई है। जिससे वन्य जीवों के लिए भीषण गर्मी में चारा-पानी का भी इंतजाम हो गया है। गौरतलब है कि गर्मी के प्रारंभ में जंगल के ज्यादातर पेड़ों के पत्ते सूखकर झड़ जाते हैं। जिससे जंगल सूखा हुआ दिखने लगता है। ऐसे हालात में जंगल के जानवरों को जंगल में चारा-पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। जिससे हर बार गर्मी के सीजन में उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालात बदतर हो जाते हैं। इस बार बार हुई बारिश की वजह से जंगल के सूखे हुए पेड़ फिर से हरे-भरे हो गए है। जंगल में घास उगने के साथ-साथ कुछ पानी के इंतजाम भी हो गए हैं।

बाहर निकल रहे हैं वन्य जीव - मौसम का मिजाज तल्ख होते ही हिंसक वन्य जंगल से बाहर निकल कर रिहायशी इलाके में पहुंचने लगे हैं। जिससे शिकार की आशंका बढ़ गई है।

बढ़ाई गई गश्त- इस बाबत वाल्मीकिनगर रेंजर महेश प्रसाद ने बताया कि मूल रूप से ये वन्य जीव स्वतंत्र होते हैं और जब उन्हें महसूस होता है कि संपूर्ण परिवेश शांत है तो वे बाहर आने लगते हैं। लेकिन, अब चूंकि, माहौल शांत है तो वे सड़कों पर पहुंच जाते हैं। हालांकि, यह वन विभाग के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण हैं। क्योंकि वाहनों की आवाजाही नहीं होने और चारों तरफ वीरानी का फायदा उठाकर शिकारी जानवरों के शिकार की तलाश में रहते हैं। विभाग ने इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दिवा गश्त के साथ- साथ रात्रि गश्त बढ़ाने जैसे कई कदम उठाए हैं।

सीएम नीतीश ने बुलाई मीटिंग तो कार से उतर पेट्रोल पंप पर बैठ गए उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद

कटिहार । कोरोना संकट के कारण उत्पन्न स्थिति तथा लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा सोमवार को मंत्रिमंडलीय सहयोगी व उच्चाधिकारियों की वर्चुअल मीटिंग में उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को पटना जाने के दौरान नवगछिया के समीप एक पेट्रोल पंप पर बैठकर वीडियो कांफ्रेंसिंग में शामिल होना पड़ा। डिप्टी सीएम अपने दो दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे थे। सोमवार को अपराह्न चार बजे वे मिरचाईबाड़ी स्थित अपने आवास से सड़क मार्ग से पटना के लिए रवाना हुए। इस बीच वर्चुअल मीटिंग के लिए नेटवर्क डिस्टर्ब होने के कारण उपमुख्यमंत्री से सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा था।

मुख्यमंत्री सचिवालय से जिलाधिकारी से इस संबंध में संपर्क किया गया। डीएम ने उपमुख्यमंत्री के पटना के लिए रवाना होने की बात कही। जिलाधिकारी ने स्वयं अपने मोबाइल से उपमुख्यंत्री से संपर्क करने की कोशिश की। डीएम व सदर एसडीओ ने वाट्सएप के जरिए भी संवाद कायम करने की कोशिश की। तमाम कोशिश के बाद भी उपमुख्यमंत्री से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा था। बाद में लैंड लाइन से डिप्टी सीएम से बात हो सकी। तब तक उनका कैरिकेड नवगछिया के समीप पहुंच गया था। एनआइसी से ओटीपी जेनरेट कर उपमुख्यमंत्री को दिया गया। नेटवर्क नहीं मिलने के कारण डिप्टी सीएम को एनएच पर आगे-पीछे भी जाना पड़ा। एक पेट्रोल पंप के समीप नेटवर्क मिलने पर उपमुख्यमंत्री वहीं बैठ वीसी में शामिल हुए। डिप्टी सीएम के एक करीबी ने बताया कि कुछ देर बाद ही नेटवर्क फिर धोखा दे गया। समीप के एक चाय दुकान के पास नेटवर्क कवरेज में आने के बाद डिप्टी सीएम वीसी से जुड़े। करीब एक घंटे तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद उपमुख्यमंत्री पटना के लिए रवाना हुए। कोरोना व लॉकडाउन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होने के कारण उपमुख्यमंत्री से संपर्क नहीं हो पाने के कारण प्रशासनिक महकमे में भी कुछ देर के लिए हलचल मची रही। प्रशासनिक अधिकारी भी इस समस्या को लेकर चिंतित दिखे।

मुख्यमंत्री योगी ने कोरोना को परास्त करने में किसानों का भी मांगा साथ, गेहूं खरीद व भुगतान की दी जानकारी

लखनऊ । किसान हितों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से भी कोरोना को परास्त करने के लिए सहयोग मांगा है। वर्चुअल चर्चा में गेहूं खरीद केंद्र, खरीद और भुगतान की जानकारी लेने के साथ ही सीएम ने किसानों का आह्वान किया कि स्वयं, परिवार और समाज को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुरक्षित रखें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से मंगलवार को किसानों के साथ वर्चुअल चर्चा में कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार पूरी शक्ति और संसाधनों से कोरोना के विरुद्ध संघर्ष कर रही है। यह समय जीवन, जीविका और मानवता को बचाने का है। सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तेजी से चल रही है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण तीव्र होने के बावजूद गेहूं क्रय अभियान के तहत लगभग 1422340.76 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा गया है, जो पिछले वर्ष से दोगुना अधिक है।

क्रय केंद्रों पर किसानों को न हो कोई समस्या : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश व देश की प्रगति-समृद्धि में किसानों के पुरुषार्थ और परिश्रम के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना का यह कालखंड किसानों की उपज की खरीद का भी समय है। सीएम योगी ने गेहूं क्रय केंद्र प्रभारियों व अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को क्रय केंद्रों पर किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। किसानों से समन्वय बनाते हुए और कोविड से सुरक्षा के प्रति जागरूक रहते हुए, पारदर्शिता व ईमानदारी के साथ अपने काम करें। इस समय कभी-कभी होने वाली बारिश को देखते हुए गेहूं को भीगने से बचाने के भी प्रबंध किए जाएं।

82 फीसद किसानों को गेहूं मूल्य का भुगतान : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को आश्वस्त किया कि क्रय केंद्रों पर कोविड संक्रमण को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस समय लगभग छह हजार केंद्र संचालित हैं। किसानों को गेहूं खरीद का भुगतान 72 घंटे के दौरान किया जा रहा है। 82 फीसद से अधिक किसानों को गेहूं मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। प्रतिदिन 90000 से एक लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा रही है। गेहूं खरीद का अभियान 15 जून, 2021 तक चलेगा।

एजेंसियों के माध्यम से गेहूं खरीद :मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, वाराणसी, बागपत, शाहजहांपुर, अलीगढ़, बाराबंकी, झांसी और मुजफ्फरनगर के किसानों से संवाद किया। इस दौरान खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सात क्रय केंद्र एजेंसियों के माध्यम से गेहूं खरीद की जा रही है। ई-पॉप मशीनों की व्यवस्था की गई है। अब तक दो लाख 69 हजार 737 किसानों को लाभान्वित किया गया है। वेबिनार का संचालन प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीना ने किया।

लॉकडाउन की पहली सुबह में बाजारों में रही भीड़, शिवहर शहर में चला पुलिस का डंडा

शिवहर । लाकडाउन की पहली सुबह शिवहर शहर में लोगों की भीड़ उमड़ी रही। बुधवार की सुबह सात बजते ही शहर की अधिकांश दुकानें खुल गई। वहीं खरीदारी के लिए दुकानों पर ग्राहकों की कतारें लग गई। इस दौरान ग्राहकों की उमड़ी भीड़ में कोविड गाइडलाइन गुम होता दिखा। कुछ हद तक लोग मास्क लगाए जरूर नजर आए। लेकिन शारीरिक दूरी पालन जैसी कोई तस्वीर नहीं दिखी। लोग बेखौफ नजर आए। साथ ही एक-दूसरे के करीब आकर खरीदारी करते नजर आए।

शिवहर शहर के जीरोमाइल, मेन रोड, गुदरी बाजार, राजस्थान चौक, थाना रोड, रजिस्ट्री आफिस चौक, सिनेमा रोड, कुशहर रोड और समाहरणालय के आसपास के इलाकों में जबरदस्त भीड़ दिखी। बाइक और कार का भी परिचालन होता दिखा। सब्जी और फल मंडी में जबरदस्त भीड़ रही। रमजान को लेकर ग्राहकों की संख्या अधिक रही। उधर, कोविड गाइडलाइन और लाकडाउन का पालन कराने के लिए अधिकारियों की टीम अलसुबह ही सड़क पर उतर गई। एसडीओ मो. इशितयाक अली अंसारी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने शारीरिक दूरी पालन और मास्क की अनिवार्यता को अभियान चलाया।

वहीं शहर के बाजारों में उमड़ी भीड़ को नियंत्रित किया। उधर, शिवहर शहर में नगर थानाध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद के नेतृत्व में निकली पुलिस की टीम ने सख्ती बरती। इस दौरान बेवजह घर से निकले लोगों को खदेड़ कर भगाया। साथ ही टेंपो चालकों पर लाठियां चटकाए। शिवहर शहर के अलावा पिपराही, पुरनहिया, तरियानी और डुमरी कटसरी के इलाकों में भी प्रशासनिक टीम गश्त लगाती रही।

बताते चलें कि, बिहार सरकार द्वारा मंगलवार की आधी रात से 15 मई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू किया गया है। इसके तहत सुबह सात से 11 बजे तक ही आवश्यक खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, मांस-मछली, दूध व पीडीएस की दुकान खोलने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा सरकारी-गैर सरकारी अस्पताल, पशु अस्पताल, दवा दुकान, एंबुलेंस सेवा व मेडिकल से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। शेष सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय, स्कूल व कोचिंग बंद रहेंगे।

एटा के एएसपी क्राइम राहुल कुमार की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत, पुलिस महकमे में शोक

आगरा । एटा के एएसपी क्राइम राहुल कुमार की कोरोना से मौत हो गई। वे 45 वर्ष के थे। चार दिन पूर्व पाजिटिव आने पर सरकारी आवास पर ही होम आइसोलेट हो गए थे। बुधवार सुबह उनकी हालत अधिक खराब हुई तो उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लाया गया जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एएसपी राहुल कुमार मूल रूप से इलाहबाद के रहने वाले थे। पिछले सप्ताह भाई की कोरोना से मौत हो गई थी उस समय अपने घर गए थे। यहां आकर कुछ तबियत खराब हुई तो जांच कराई जिसमें पाजिटिव पाए गए। इसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को दिल्ली भेज दिया और खुद आइसोलेट हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कल रात तक खुद को ठीक महसूस कर रहे थे। बुधवार सुबह उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई तो अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को जानकारी दी। सरकारी आवास पर तैनात पुलिसकर्मी तत्काल उन्हें जिला अस्पताल ले आए जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उधर परिवार को जब सूचना मिली तो इलाहबाद और दिल्ली से परिवार के सदस्य एटा के लिए रवाना हो गए। एसएसपी उदय शंकर सिंह, जिलाधिकारी डा. विभा चहल समेत जिले भर के आला अफसर जिला अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में तमाम पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा है। परिवार का इंतजार हो रहा है। एएसपी ने अपने पीछे दो बच्चों और पत्नी को विलखते हुए छोड़ा है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस परिवार के लिए यह बेहद दुख की घड़ी है। एएसपी के निधन से अपूर्णनीय क्षति हुई है।

मृदुभाषी थे राहुल

एसएसपी राहुल कुमार व्यवहार कुशल और मृदुभाषी थे। उन्होंने यहां रहते हुए हर पीड़ित की मदद की। तथा सर्विलांस की उन्हें अच्छी जानकारी थी। तमाम जटिल से जटिल केस उन्होंने निपटाए। उच्च अधिकारी उनसे सर्विलांस के मामले में मदद लेते थे। हाल ही में देहात कोतवाली के शराबकांड के खुलासे का श्रेय भी राहुल के ही नाम रहा। इस कांड ने पूरे अलीगढ मंडल में हलचल मचा दी थी।

यूपी में कोविड प्रोटोकॉल के साथ राशन वितरण, अंत्योदय कार्डधारकों को मिलेगा 35 किलो खाद्यान्न

लखनऊ । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बुधवार से 14 मई तक अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। आयुक्त खाद्य व रसद मनीष चौहान ने जिलाधिकारियों व जिला पूर्ति अधिकारियों को उचित दर विक्रेतावार अधिकारियों की तैनाती कर निगरानी के निर्देश दिए हैं। कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ राशन वितरित किया जाएगा। आयुक्त खाद्य व रसद मनीष चौहान ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 20 किलो गेहूं व 15 किलो चावल शामिल है, वितरित किया जाएगा। इसी तरह पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें तीन किलो गेहूं व दो किलो चावल वितरित किया जाएगा। गेहूं का वितरण मूल्य दो रुपये प्रति किलो तथा चावल का मूल्य तीन रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। वितरण के लिए टोकन सिस्टम लागू करते हुए एक दुकान पर एक समय में पांच से अधिक उपभोक्ता न रहने देने की हिदायत दी गई है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा- ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत नरसंहार से कम नहीं

प्रयागराज । उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए नाराजगी जताई है। अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से कोविड-19 मरीजों की मौत को आपराधिक कृत्य करार देते हुए नरसंहार बताया है। कोर्ट ने कहा कि नरसंहार के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके ऊपर लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की जिम्मेदारी थी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब विज्ञान इतनी उन्नति कर गया है कि इन दिनों हृदय प्रतिरोपण और मस्तिष्क की सर्जरी की जा रही है, ऐसे में हम अपने लोगों को इस तरह से कैसे मरने दे सकते हैं। आमतौर पर हम सोशल मीडिया पर वायरल हुई ऐसी खबरों को जांचने के लिए राज्य और जिला प्रशासन से नहीं कहते, लेकिन इस जनहित याचिका में पेश अधिवक्ता इस तरह की खबरों का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हमारा सरकार को तत्काल इस संबंध में कदम उठाने के लिए कहना आवश्यक है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने राज्य में संक्रमण के प्रसार और पृथक-वास केन्द्र की स्थिति संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी से हुई कोविड-19 मरीजों की मौत से जुड़ी खबरों पर संज्ञान लेते हुए लखनऊ और मेरठ के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इनकी 48 घंटों के भीतर तथ्यात्मक जांच करें। अदालत ने दोनों जिलाधिकारियों से कहा है कि वे मामले

की अगली सुनवाई पर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करें और अदालत में ऑनलाइन उपस्थित रहें।

हाई कोर्ट ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से कोविड रोगियों की मृत्यु दर्दनाक है और इसकी आपूर्ति के लिए उन लोगों द्वारा नरसंहार से कम नहीं है, जिन्हें इसकी निरंतर खरीद और आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। कोर्ट ने पाया कि इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने वाली खबरों में नागरिक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भीख मांगते हुए दिखे हैं ताकि वे अपने करीबियों के जान बचा सकें, जबकि इसके लिए जिम्मेदारों की ओर से उन्हें परेशान किया गया।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मेरठ मेडिकल कॉलेज के नए ट्रॉमा सेंटर के आइसीयू में ऑक्सीजन नहीं मिलने से पांच मरीजों की मौत की खबर इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई है। इसी तरह लखनऊ के गोमती नगर में सन हॉस्पिटल और एक अन्य निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से डॉक्टरों के कोविड मरीजों से अपनी व्यवस्था खुद करने की खबरें भी वायरल हुई हैं। अवैध रूप से जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन/गोलियां और ऑक्सीमीटर को मालखाने में रखे जाने पर अदालत ने कहा इन वस्तुओं को मालखाने में रखना किसी भी तरह से जनहित में नहीं है क्योंकि ये सभी खराब हो जाएंगे। इस पर गोयल ने कहा कि वह इस मुद्दे को राज्य सरकार के समक्ष उठाएंगे ताकि इनका उचित उपयोग हो सके और ये बेकार ना जाएं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश वीके श्रीवास्तव की संक्रमण से मृत्यु पर अदालत ने कहा कि हमें बताया गया है कि न्यायमूर्ति श्रीवास्तव को 23 अप्रैल की सुबह लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शाम तक उनकी देखभाल नहीं की गई। शाम 7-30 बजे हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और उसी रात उन्हें एसजीपीजीआई में ले जाया गया जहां वह पांच दिन आइसीयू में रहे और उनकी कोरोना संक्रमण से असामयिक मृत्यु हो गई। अदालत ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से कहा है कि वह हलफनामा दाखिल कर बताएं कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव का क्या इलाज हुआ और उन्हें 23 अप्रैल को ही एसजीपीजीआइ क्यों नहीं ले जाया गया?

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि राज्य में ग्राम पंचायत चुनावों की मतगणना के दौरान कोविड दिशानिर्देशों का भारी उल्लंघन किया गया। लोग मतगणना स्थलों पर भारी संख्या में एकत्रित हुए और चुनाव अधिकारी एवं पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इस पर अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को सुनवाई की अगली तारीख 7 मई, 2021 को लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और आगरा में मतगणना केंद्रों का सीसीटीवी फुटेज पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा, हम यहां स्पष्ट करते हैं कि साथ ही यदि आयोग सीसीटीवी फुटेज से यह पाता है कि कोविड प्रोटोकॉल का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है तो वह इस संबंध में कार्य योजना पेश करेगा।

बता दें कि यूपी में कोरोना संक्रमण से मरीजों की स्थिति गंभीर है। कई मामलों में ऑक्सीजन का लेवल गिरता जाता है और उन्हें बचाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और दूसरी ओर ऑक्सीजन की मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके चलते अस्पतालों में मरीज जान गंवा रहे हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण के बीते 24 घंटे में 25,858 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इस दौरान 352 लोगों की मौत भी हुई है। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 13,798 हो गया है।

लाभार्थी मुंबई में गोरेगांव में MMRC समर्पित कोविड -19 स्वास्थ्य केंद्र में टीका लगवाने के लिए लंबी कतारों में प्रतीक्षा करते हुए।

कोलकाता के राजभवन में ममता बनर्जी के शपथ समारोह के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर।

लाभार्थी गुवाहाटी में कोविड -19 वैक्सीन की अपनी पहली खुराक प्राप्त करने की प्रतीक्षा करते हुए।

एक नजर

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के सख्त निर्देश- सरकारी व वन विभाग की जमीनों पर कब्जे रोके जाए

जम्मू । सुंजवां के चाटा गांव में सरकारी व वन विभाग की जमीनों पर हो रहे कब्जों को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने राजस्व व वन विभाग को अतिक्रमण रोकने की दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया है। गांव के स्थानीय लोगों की ओर से यह जनहित याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका में कहा गया कि कुछ लोग गांव की सरकारी जमीन व वन क्षेत्र पर लगातार कब्जा कर रहे हैं और उन्होंने जल स्रोतों पर भी कब्जा कर लिया है। जम्मू जिले की बाहू तहसील के इस क्षेत्र के खसरा नंबर 852, 1441, 1442, 1445, 1447, 1452, 2198 व 2202 में ये कब्जे हुए है। जनहित याचिका में कहा गया कि स्थानीय लोगो ने 2016 में भी यह मुद्दा उठाया था और इस मामले को लेकर एक एफआइआर भी दर्ज हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 2019 में भी स्थानीय लोगों ने इस मामले को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा लेकिन सब व्यर्थ हुआ। अब 11 अप्रैल 2021 को स्थानीय लोगों ने एक बैठक की और इस मामले को कोर्ट के समक्ष रखने का फैसला लिया। जनहित याचिका में आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने व सरकारी व वन विभाग की जमीन पर हुए कब्जों को खाली करवाने की मांग की गई। बेंच ने इस पर जीएडी, राजस्व व वन विभाग के आयुक्त सचिव, जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर, जेडीए के वाइस चेयरमैन, जम्मू के डिप्टी कमिश्नर व अन्य को नोटिस जारी कर अवैध कब्जों को रोकने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए। बेंच ने कहा कि अगर इस दिशा में कोई कदम उठाया गया है, तो उसकी रिपोर्ट भी पेश की जाए।

राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कोरोना से पिता की मौत, चिता पर कूदी बेटी, 70 फीसदी झुलसी

जयपुर । राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित श्वदाह गृह में मंगलवार को कोरोना की डरावनी तस्वीर देखने को मिली। यहां कोरोना शिकार एक व्यक्ति की मौत पर उसकी तीन बेटियों ने मुखाग्नि दी । मुखाग्नि देने के बाद एक बेटी अचानक पिता की चिता पर यह कहते हुए कूद गई कि पापा मेरे सब कुछ थे, वे नहीं रहे तो अब मैं जीवित रह कर क्या करूंगी । यह सबकुछ इतने जल्दी हुआ कि मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं सके।

अचानक हुई इस घटना के बाद लोगों ने जैसे-तैसे युवती को पिता की चिता से खींचा और अस्पताल लेकर गए । युवती 70 फीसदी तक झुलस गई । उसकी स्थिति ज्यादा खराब बताई जा रही है । बाड़ेमेर की राय कॉलोनी में रहने वाले 65 साल के दामोदर शारदा कोरोना संक्रमित हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार को उनकी मौत हो गई । मौत के बाद उनकी तीनों बेटियों ने श्वदाह गृह विकास समिति के सहयोग से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की । इसी दौरान उनकी एक बेटी चंद्रा पिता की चिता पर कूद गई,जो अब अस्पताल में भर्ती है। श्मशान विकास समिति के संयोजक भैरूसिंह ने बताया कि यह घटना मंगलवार शाम करीब 4 बजे हुई । उधर परिजनों ने बताया कि मृतक शारदा दिव्यांग थे। उन्हे कुछ समय पूर्व एक पेट्रोल पंप आवंटित हुआ था । आवंटन के कुछ दिन बाद ही प्रशासन ने दस्तावेजों की कमी बताते हुए पेट्रोल पंप सील कर दिया था । वे पेट्रोल पंप की सील खुलवाने के लिए संघर्ष कर रहे थे कि अचानक कोरोना के शिकार हो गए और इसी से मौत हो गई ।

सुप्रीमकोर्ट ने मराठों को नौकरी और शिक्षा में दिया जाने वाला आरक्षण असंवैधानिक ठहराया

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठाओं के लिए आरक्षण के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीमकोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठों को नौकरी और शिक्षा में दिया जाने वाला आरक्षण असंवैधानिक ठहराया। साथ ही कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम 50 फीसद सीमा तय करने वाले 1992 के इंदिरा साहनी फैसले को पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजने की मांग भी ठुकराई। पांच जजों वाली संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि मराठाओं को कोटा देने वाले महाराष्ट्र के कानून में 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करता है। मराठा आरक्षण देते समय 50 फीसद आरक्षण का उल्लंघन करने का कोई वैध आधार नहीं था फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि मराठा समुदाय के लोगों को शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय के रूप में घोषित श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है। बांबे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठाओं के लिए आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा था। इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने 26 मार्च को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। संविधान पीठ ने मामले में सुनवाई 15 मार्च को शुरू की थी। उच्च न्यायालय ने जून 2019 के कानून को बरकरार रखते हुए कहा था कि 16 प्रतिशत आरक्षण उचित नहीं है। रोजगार में आरक्षण 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा नामांकन में यह 13 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

ममता की शपथ के बीच गवर्नर जगदीप धनखड़ ने दी राष्ट्रपति शासन की चेतावनी, कहा- हिंसा नहीं रुकी तो...

कोलकाता । टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई हैं। उन्हें गवर्नर जगदीप धनखड़ ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक तरफ गवर्नर ने दीदी को तीसरी बार राज्य के सीएम के तौर पर शपथ दिलाई तो उससे कुछ वक्त पहले ही उन्होंने एक ट्वीट किया। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया, ममता बनर्जी, कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस से मसले को उठाने के बाद भी राज्य में चुनाव के बाद जारी हिंसा थम नहीं रही है। इस तरह की हिंसा लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। राज्य में कानून और व्यवस्था के हालात इस तरह से बिगड़ने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्य में ऐसे हालात जारी नहीं रह सकते।

गवर्नर जगदीप धनखड़ के इस ट्वीट को राज्य में उनकी ओर से राष्ट्रपति शासन लगाने की चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले सोमवार को गवर्नर जगदीप धनखड़ ने राज्य के डीजीपी से बात की थी और चुनाव के बाद जारी हिंसा को लेकर चिंता जताई थी। यही नहीं उन्होंने मंगलवार को बताया था कि पीएम नरेंद्र मोदी की उनसे बात हुई है और उन्होंने बंगाल में जारी हिंसा को लेकर चिंता जताई है। इस बीच चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने चुनाव के बाद जारी हिंसा को रोकने की अपील की है। बता दें कि 2 मई को विधानसभा चुनाव के परिणामों में टीएमसी की जीत का ऐलान होने के बाद से ही राज्य में हिंसा का दौर जारी है। बीजेपी की ओर से नंदीग्राम, दक्षिण 24 परगना समेत राज्य के कई हिस्सों में टीएमसी पर हिंसा का आरोप लगाया गया है। हिंसक घटनाओं के बाद मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दो दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे हैं। उन्होंने राज्य में हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात की है।

बीएसएफ ने रासायनिक पदार्थ व मछली के लार्वा की तस्करी करते दो तस्कर रंगे हाथ किए गिरफ्तार

कोलकाता । दक्षिण बंगाल फ्रंटियर, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने उत्तर 24 परगना जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास से रासायनिक पदार्थ फॉर्मालीन और मछली के लार्वा (मत्स्य डिंब) की पड़ोसी देश में तस्करी करते दो तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बीएसएफ की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि तस्करों के पास से पांच लीटर फॉर्मालीन और एक पॉलीबैग मत्स्य डिंब जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2,500 रुपये है।

बीएसएफ की सीमा चौकी घोजाडांगा, 153वीं वाहिनी के क्षेत्र से अवैध तरीके से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कराकर बांग्लादेश में इसकी तस्करी की कोशिश की जा रही थी। बयान के मुताबिक, दो मई को प्राप्त खुफिया सूचना पर कार्य करते हुए सीमा चौकी घोजाडांगा, 153वी वाहिनी, सेक्टर कोलकाता के जवानों ने इटिंडा- उत्तरपाड़ा सड़क के पास एक स्पेशल पट्रोलिंग निकाली।

इस दौरान जवानों ने दो संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार की हरकत देखी जो आईसीपी ब्रिज से होकर घोजाडांगा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही मोटरसाइकिल सवार आईसीपी ब्रिज के नजदीक आए, पहले से मुस्तैद सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बिना कोई मौका दिए दोनों को पकड़ लिया।

जब पेट्रोलिंग पार्टी ने मोटरसाइकिल की तलाशी ली तो इसके अंदर से पांच लिटर रासायनिक पदार्थ और एक पॉली बैग मत्स्य डिंब बरामद किया गया। शीघ्र ही जवानों ने उक्त सामग्री के साथ साथ मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया तथा दोनों तस्करों को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए तस्कर की पहचान कमाल मंडल (18) तथा समर सरकार (29) के रूप में हुई है। दोनों ही ग्राम- उत्तरपाड़ा, पोस्ट- पानीतार, थाना- बशीरहाट, जिला- उत्तर 24 परगना का निवासी है।

दोनों पहले से तस्करी के कार्य में रहा है शामिल- पूछताछ के दौरान पकड़े गए तस्करों ने बताया कि वे दोनों ही भारतीय नागरिक है तथा पिछले कुछ दिनों से मत्स्य डिंब तथा अन्य प्रकार की तस्करी मे शामिल है। आज वह इन सभी रासायनिक पदार्थ और पॉलीबैग मत्स्य डिंब को इटिंडा बाजार में बशीरहाट निवासी हसन गाजी तथा राजू मंडल से लिया था तथा आगे आईसीपी घोजाडांगा ब्रिज क्रॉस करने के पश्चात इसे बांग्लादेश में पहुंचना था। उसने यह भी बताया कि इन मत्स्य डिंब को बांग्लादेश में एक्सोटीक बर्ड्स के साथ बदल कर वापस भारत में सुंदर पक्षियों की तस्करी का कार्य करता है। गिरफ्तार तस्करों तथा जब्त की गई रासायनिक पदार्थ और मत्स्य डिंब को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए बशीरहाट पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है।

बीएसएफ कमांडेंट ने थपथपाई जवानों की पीठ - इधर, 153वीं बटालियन, बीएसएफ के कमांडिंग ऑफिसर जवाहर सिंह नेगी ने अपने जवानों की उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप इस प्रकार के प्रतिबंधित सामान की तस्करी को नाकाम करते हुये दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि यह केवल ड्यूटी पर तैनात उनके जवानों द्वारा प्रदर्शित सतर्कता के कारण ही संभव हो सका है।

तपती धूप में फिर पैदल आने को मजबूर, पिछले एक सप्ताह में पांच हजार से अधिक मजदूर लौटे अपने गांव

उदयपुर । आदिवासी जिले के डूंगरपुर के एक लाख से अधिक लोग गुजरात तथा महाराष्ट्र में मजदूरी करते हैं। पिछले साल लगे लॉकडाउन में 60 फीसदी से अधिक मजदूरों को फिर से काम नहीं मिल पाया। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते गुजरात तथा महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसे हालात की वजह से एक बार फिर उन्हें अपने घरों पर लौटना पड़ रहा है। रतनपुर बार्डर पर प्रवेश को लेकर बढ़ाई सख्ती तथा आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के अभाव में मजदूर तपती दोपहरी में पैदल ही सड़क नापने को मजबूर हो रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में पांच हजार से अधिक मजदूरों ने डूंगरपुर जिले में कच्चे रास्तों के जरिए प्रवेश किया और अपने घरों पर लौटे।

रतनपुर बार्डर पर उन्हीं लोगों को राजस्थान की सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है, जिनकी तीन दिन पहले कराई गई आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई हो और वह वैक्सीनेशन करा चुके हो। ऐसे में जिन मजदूरों ने अपनी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं कराई और वैक्सीनेशन नहीं कराया, वह उलटे पांव लौटने को मजबूर हैं। काम नहीं मिलने तथा भूखे मरने की नौबत के चलते वह अपने घरों के लिए तपती धूप में पैदल चलने को मजबूर होने लगे हैं। इसके लिए वह कच्चे रास्तों को अपना रहे हैं, जहां उन्हें रोकने वाला कोई नहीं।

बार्डर से पहले पैदल रास्ता की ओर रूख कर लेते- डूंगरपुर के आसपुर क्षेत्र के नरेंद्र खराड़ी का कहना है कि मंगलवार को वह अपने परिवार के साथ गुजरात से घर लौटा है। सूरत में काम करता था लेकिन वहां लॉकडाउन की जैसी स्थिति के चलते उसके मालिक ने उसे घर जाने के लिए कह दिया। वहां रूकने के लिए पैसा चाहिए, जो खत्म होने लगा। उसके जैसे सैकड़ों लोग अपने घरों के लिए लौट रहे थे। वाहनों के जरिए वह निकले लेकिन रतनपुर बार्डर पर कड़ी चैकिंग की सूचना पर आधा किलोमीटर पहले ही वह उतर गए। वहां से कच्चे रास्तों के जरिए पैदल ही यात्रा की और डूंगरपुर जिले में पहुंचे। उसने बताया कि सूरत, अहमदाबाद तथा गुजरात के कई शहरों में जिले के हजारों मजदूर काम करते हैं। पिछले एक सप्ताह में सर्वाधिक मजदूर घर लौटे। जिनकी संख्या पांच हजार से अधिक ही होगी। सागवाड़ा निवासी रमेश खांट भी दो दिन पहले गुजरात से परिवार सहित लौटा। जिसने बताया कि वहां के उद्योग-धंधों पर काम नहीं मिल पा रहा, ऐसे में घर लौटना मजबूरी थी। गुजरात में खर्चा उठाने तथा आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के लिए भटकने की जगह घर लौटना ज्यादा आसान लगा।

बार्डर पर सघन चैकिंग जारी

डूंगरपुर के जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी का कहना है कि रतनपुर बार्डर पर सघन चैकिंग जारी है। बिना नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। कच्चे रास्तों से पैदल आने की सूचना है। वाहनों के प्रवेश पर लगाम लगाया जा सकता है लेकिन मजदूरों के पैदल आने से रोकना संभव नहीं।

अस्थायी क्वारेनटाइन स्थल बनाए जाने की जरूरत- पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी का कहना है कि बार्डर पर अस्थायी क्वारेनटाइन स्थल बनाया जाना चाहिए। जहां गुजरात तथा अन्य राज्यों से आने वाले ऐसे लोगों को रोका जाए, जिन्होंने आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं कराई। साथ ही उनकी यहां कोरोना की जांच कराई जाए और जिन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आएं, उन्हें घर जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाए तो आसान होगा। पिछले साल भी इसी तरह व्यवस्था की गई थी और आसानी हुई।

ऐसे कैसे हारेगा कोरोना- भारत के अधिकतर जिलों में 10प्रतिशत से भी कम हुआ टीकाकरण

नई दिल्ली । भारत में कोरोना से तबाही चरम पर है। इसकी गति को धीमा करने का एक मात्र रास्ता टीकाकरण नजर आता है। हालांकि टीकाकरण अभियान शुरु हुए तीन माह हो चुके हैं लेकिन अभी तक बेहद कम लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैक्सीन रोलआउट की संख्या दर्शाती है कि समीक्षा किए गए 726 जिलों में से केवल 37 (सिर्फ 5 प्रतिशत) ने अब तक टीके की कम से कम एक खुराक 20 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों को दी है। कोविन एप के डेटा के अनुसार पुडुचेरी का माहे और गुजरात का जामनगर दो ऐसे जिले हैं जहां सबसे अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। डेटा के अनुसार इन जिलों में एक तिहाई जनसंख्या को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है।

वहीं बड़ी संख्या में ऐसे जिले हैं जहां वैक्सीनेशन प्रक्रिया का हाल बुरा है। लगभग 58 प्रतिशत जिलों में 10 प्रतिशत से भी कम बै जबकि 37 प्रतिशत जिलों में ये 10 से 20 प्रतिशत के बीच है। कर्ना का बीजापुर और असम का सलमारा दो ऐसे जिले हैं जहां सबसे कम टीकाकरण हुआ है। एप के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कई जिलों में 10 प्रतिशत से कम आबादी का टीकाकरण हुआ है। इधर, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के कई जिलों में 10 प्रतिशत से अधिक आबादी को टीके लगाए गए हैं। पूरे भारत में फिलहाल लगभग दस फीसदी आबादी को टीके की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। देश में टीकाकरण की रफ्तार इतनी धीमी है कि अगली दस प्रतिशत आबादी को पहली खुराक देने में कम से कम 117 दिन लगेंगे। रॉयटर्स का टीकाकरण ट्रैकर तो कुछ ऐसा ही दावा कर रहा है। इसके मुताबिक, पिछले सप्ताह टीकाकरण की रफ्तार में खासी कमी आयी है।

दो फीसदी से कम भारतीयों का पूर्ण टीकाकरण- भारत में 9.3 फीसदी आबादी को कोविड-19 टीके की पहली खुराक मिल चुकी है। वहीं, दोनों खुराक लेकर पूर्ण टीकाकरण करा चुके लोगों की संख्या अभी दो फीसदी का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। रॉयटर्स के मुताबिक भारत में पिछले हफ्ते रोजाना औसतन 2337141 टीके लगाए गए। हालांकि, यह दर देश में सबसे तेज टीकाकरण की साप्ताहिक दर से 35त्न कम रही। इस आधार पर रॉयटर्स के गणितीय मॉडल का अनुमान है कि भारत को अगली दस प्रतिशत आबादी को टीके की पहली खुराक देने में 117 दिन लगेंगे।

चार दिन बाद खुली थोक अनाज मंडियां, विभिन्न जिलों में भेजी गई राशन सप्लाई

जम्मू । जम्मू में वीरवार रात से लगे लॉकडाउन के चलते पिछले चार दिन से बंद पड़ी थोक अनाज मंडियां सुबह चार घंटे के लिए खुली। मंडियां खुलने के साथ ही यहां से जम्मू समेत अन्य जिलों में राशन की सप्लाई शुरू हुई। चार दिन तक थोक अनाज मंडियों के बंद रहने से जम्मू समेत अन्य जिलों में राशन की किल्लत बनने लगी थी जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने मंगलवार से इन मंडियों में भी राशन की थोक दुकानों को सुबह छह बजे से दस बजे तक खुलने की अनुमति दी थी। ये मंडिया चूंकि चार दिन बाद खुली थी, लिहाजा मंगलवार को यहां पर सामान्य दिनों की तुलना में अधिक कामकाज देखा गया।

जम्मू की सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयर हाउस-नेहरू मार्केट की बात करें तो यहां सुबह छह बजे से पहले ही बाहरी राज्यों से आए राशन के ट्रकों की कतारें लग गई थी। चार दिन से मंडी बंद होने के कारण ये ट्रक भी अनलोड नहीं हो पाए थे।

लिहाजा सुबह-सवेरे ही यहां पर अनलोडिंग का काम तेजी पकड़ गया। इसके बाद दुकानदारों ने विभिन्न इलाकों में राशन सप्लाई भेजना शुरू किया। मंगलवार को इस मंडी से करीब 100 ट्रक राशन विभिन्न जिलों में भेजा गया। इसके अलावा पुलिस, सेना, सीआरपीएफ व बीएसएफ की विभिन्न कंपनियों के लिए भी आज राशन सप्लाई भेजी गई। यह सप्लाई भी पिछले चार दिनों से रूकी हुई थी।

उधर पुराने शहर की कनक मंडी में भी मंगलवार सुबह किरयाना की थोक दुकानें चार घंटे के लिए खुली और खुदरा दुकानदारों ने जरूरी सामान की खरीदारी की। ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस-नेहरू मार्केट के प्रधान दीपक गुप्ता के अनुसार पिछले चार दिनों से मंडी के किरयाना दुकानदारों को विभिन्न जिलों से राशन की मांग आ रही थी। मंडी के अधिकतर दुकानदारों ने फोन पर आर्डर लिए थे ताकि दुकानदारों को मंडी में आने की जरूरत न पड़े और मंडी में भीड़ भी न हो। जिनके पास जितने आर्डर थे, उनकी सप्लाई भेजना शुरू कर दी गई है।

उपराज्यपाल सिन्हा ने दिए निर्देश- आसपास के अस्पतालों में ऑक्सीजन से जुड़े बेड की संख्या बढ़ाई जाए

जम्मू । उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहरों के आसपास के इलाकों वाले अस्पतालों में ऑक्सीजन के सिलेंडर वाले कोविड बेड की संख्या को बढ़ाया जाए। उन्होंने अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों की प्रभावी तरीके से जांच कर कोरोना का पता लगाए जाने पर जोर देते हुए कहा अस्पतालों की रेफर नीति को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।

आम लोगों तक आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुचारू होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में कोरोना से उपजे हालात की समीक्षा करते हुए उपराज्यपाल ने रोज आने वाले मामलों, टेस्ट की क्षमता , मरीजों के ठीक होने की दर और सक्रिय मामलों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने मांग के अनुसार ऑक्सीजन की सप्लाई, अस्पतालों में बेड की क्षमता, वैक्सीनेशन के अभियान और जिला आधार पर कंटेनमेंट जोन पर भी विचार विमर्श किया।

उपराज्यपाल ने निर्देश दिए कि आसपास के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर वाले बैड की संख्या को बढ़ाया जाए। उपराज्यपाल ने आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक जिसमें राशन, सब्जियां और अन्य वस्तुएं शामिल हैं, की समीक्षा की। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर ने उपराज्यपाल को बताया कि सुबह के समय में सब्जी की मंडियां खोली जाती हैं ताकि आम लोगों को सब्जी लेने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बताते चलें कि सरकार ने संकट प्रबंधन ग्रुप का गठन पहले से किया है जो कोरोना से उपजे हालात की निगरानी करके प्रभावी कदम उठा रहा है।

बैठक में मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम, वित्त विभाग के वित्त आयुक्त अरुण कुमार मेहता, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त अटल डुल्लु, गृह विभाग के प्रमुख सचिव शालीन काबरा, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव शैलेंद्र कुमार व अन्य अधिकारी शामिल थे।

बंगाल में वर्चस्व कायम रखने का हथियार रही है हिंसा, सूबे का रहा है खूनी सियासी इतिहास, जा चुकी हैं हजारों जानें

कोलकाता । बंगाल में दशकों से हिंसा के हथियार से ही सियासी वर्चस्व कामय की जाती रही है। बांग्ला में एक मशहूर कहावत है- जेई जाए लंका, सेई होए रावण अर्थात जो भी लंका जाता है, वही रावण बन जाता है। इसी कहावत के अनुरूप यहां का खूनी सियासी इतिहास है। राजनीतिक हिंसा में हजारों जानें जा चुकी है। 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार को जैसे ही घोषित हुए वैसे ही हिंसा का दौर शुरू हो गया। उन इलाकों में अधिक हिंसा हो रही है जो मुस्लिम बहुल इलाका है।

हुगली का आरामबाग हो या फिर बीरभूम जिले का नानूर या फिर शीतलकूची और दिनहाटा। जिस तरह से भाजपा समर्थकों व कार्यकर्ताओं की दुकानें लूटी गई, हत्याएं हुई है।

उसका वीडियो यह बताने को काफी है कि इस हिंसा के पीछे कौन है और क्यों पुलिस मूकदर्शक बनी है। हिंसा के इन आरोपों को सोमवार को तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी खारिज कर दिया था। परंतु, जब ममता विपक्ष में थीं तो वही वामपंथी शासन में 50 हजार हत्याएं होने की बात कहती थी और कामरेड आरोपों को नकारते थे।

भाजपा का आरोप है कि पिछले 36 घंटे में उसके नौ कार्यकर्ताओं की तृणमूल समर्थकों ने हत्या कर दी है और कई जख्मी हैं। इतना ही नहीं भाजपा का कहना है कि राज्य में विधानसभा नतीजों के बाद हिंसा तथा अन्य मामलों की 272 घटनाएं घटी हैं। यह बताने को काफी है कि मतगणना के बाद बंगाल किस तरह से लहूलुहान हो रहा है। वैसे तो बंगाल में चुनाव पूर्व या बाद हिंसा नई बात नहीं है। परंतु, इस बार कुछ अधिक हो रही है। इसकी वजह यह है कि जब-जब विपक्ष मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और सत्तारूढ़ जीती है तो हिंसा बढ़ी है। इसका प्रमाण 2001,2006 का विधानसभा चुनाव भी है।

अतीत में झांके तो 1959 के खाद्य आंदोलन के दौरान 80 लोगों की जानें गई थीं, जिसे वामपंथियों ने कांग्रेस की विपक्ष को रौंदकर वर्चस्व कायम करने की कार्रवाई करार दिया था। इसके बाद 1967 में सत्ता के खिलाफ नक्सलबाड़ी से शुरू हुए सशस्त्र आंदोलन में सैकड़ों जानें गई थीं।

1971 में जब कांग्रेसी सरकार बनीं और सिद्धार्थ शंकर रॉय मुख्यमंत्री बने तो बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का जो दौर शुरू हुआ, उसने सभी हिंसा को पीछे छोड़ दिया। कहा जाता है कि 1971 से 1977 के बीच कांग्रेस ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए हिंसा को हथियार बनाया था और यही हिंसा 1977 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पतन और माकपा नीत वाममोर्चा के उदय की वजह बनी। इसके बाद कांग्रेस का बंगाल में क्या हश्र हो हुआ, यह सर्वविदित है।

1977 में भारी बहुमत से सत्ता में आने के बाद वामपंथियों ने भी हिंसा की राह को ही अपना लिया और सियासी वर्चस्व कायम रखने के लिए हत्या व हिंसा का संगठित तरीके से इस्तेमाल शुरू कर दिया। 1977 से 2011 तक वाममोर्चा के 34 वर्षों के शासनकाल में बंगाल की सियासी फिजा पूरी तरह से लहूलुहान रही। 2007 से 2011 तक सियासी हिंसा व हत्याओं में बंगाल पूरे देश में नंबर एक पर था।

2006-07 में नंदीग्राम में 14 और सिंगुर में कई हत्याएं हुई। यह दौर वामपंथी शासन के अंत और तृणमूल के सत्ता के शिखर पर पहुंचने का था। इसके बाद 2011 में ममता सरकार सत्ता में आई, लेकिन सियासी हिंसा और हत्याओं का दौर जारी है।

2013 के पंचायत चुनाव के दौरान भीषण हिंसा हुई थी। ममता ने 2011 के विधानसभा चुनाव में नारा दिया था-'बदला नहीं...बदल चाहिए', लेकिन हुआ उसके विपरीत। बंगाल में जो रवायत रही है उस अनुसार यह हिंसा इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है। यह तब तक जारी रहेगी जब तक भाजपा को कमजोर नहीं किया जा सकेगा।

मददगार सितारे

श्वेता बसु प्रसाद सत्यजीत रे की जन्मशताब्दी पर बनाई अपनी पेंटिंग कर रहीं नीलाम

कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए देंगी पैसा

श्वेता ने सोशल मीडिया पर पेंटिंग की नीलामी के बारे में बताया है। नीलामी 60 हजार रुपए से शुरू की है। श्वेता लिखती हैं- पेंटिंग ऑन सेल फॉर कोविड फंड्स, एक्रिलिक ऑन कैनवास। मैं एक खुद से सीखी हुई पेंटर हूं। कृपया मेरे प्रयास को देखें। मैं एक कलाकार हूं। मैं घर पर बैठकर लोगों की मदद करने का और कोई रास्ता नहीं जानती, जबकि मैं वाकई मदद करना चाहती हूं। हैप्पी बर्थडे रे।

3 दिन तक ओपन रहेगी बिडिंग - गौरतलब है कि फिल्म इंडस्ट्रीज में सत्यजीत रे का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। 2 मई को उनके जन्म के सौ साल पूरे हो गए हैं। श्वेता ने लिखा- सत्यजीत रे ने कहानियां लिखीं और आम आदमी के बारे में फिल्में बनाईं, यह सही है कि मैं आज उनकी जन्म शताब्दी पर यह पहल कर रही हूं। श्वेता ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा है कि यह नीलामी 3 दिन तक ओपन रहेगी।

पेंटिंग के लम्हे भी शेयर किए

श्वेता ने इस पेंटिंग को बनाने के लम्हे भी शेयर किए हैं। जिसमें वे पेंटिंग बनाते हुए दिखाई दे रही हैं। श्वेता ने लिखा है कि इस पेंटिंग का कॉपीराइट रिजर्व है। श्वेता ने इसमें सत्यजीत रे की ऑस्कर ट्रॉफी और कैमरे के साथ उनके लिखे अमर किरदार भी दिखाए हैं। श्वेता ने इसे 2 मई के दिन ही तैयार किया है। बात अगर श्वेता के फिल्मी कॅरियर की करें तो वे मकड़ी, मकबूल, द ताशकंद फाइल्स जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।

कोविड पॉजिटिव हिना ने पिता को खोने के बाद इमोशनल होकर लिखा-

मैं वो लाचार बेटी हूं जो मां के साथ भी नहीं रह सकती

कोरोना की दूसरी लहर जहां एक तरफ पूरे देश के लिए भयानक साबित हुई है वहीं हिना खान के लिए ये दुख पिता के गुजरने और खुद कोरोना पॉजिटिव होने से दोगुना हो चुका है। एक्ट्रेस के पिता का निधन 20 अप्रैल को हार्ट अटैक से हो हुआ था जिसके बाद एक्ट्रेस खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। रिपोर्ट आने के बाद से ही हिना अपनी मां से दूर अकेले क्वारैंटाइन हो चुकी हैं। इस मुश्किल समय में मां से दूर रहने पर एक्ट्रेस ने इमोशनल होकर एक नोट शेयर किया है। हिना खान ने सोशल मीडिया पर अपने क्वारैंटाइन मूमेंट की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, एक लाचार बेटी, जो अपनी मां को सहारा देने के लिए उनके साथ भी नहीं रह सकती, जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, ये समय बहुत कठिन है, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आसपास के हर व्यक्ति के लिए। लेकिन कहा जाता है, बुरा वक्त ज्यादा समय तक नहीं रहता, लेकिन हिम्मत वाले लोग हमेशा रहते हैं, और मैं हमेशा से अपने पिता की स्ट्रॉन्ग गर्ल थी, हूं और हमेशा रहूंगी। अपनी दुआ भेजते रहिए प्लीज।

सोशल मीडिया से बनाई दूरी

एक्ट्रेस ने हाल ही में फैंस को जानकारी देते हुए बताया कि वो और उनका पूरी परिवार पिता के गुजर जाने के शोक में डूबा हुआ है, ऐसे में वो सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हैं। अब से उनके सभी सोशल मीडिया हैंडल उनकी टीम द्वारा अपडेट किए जाएंगे।

सेलेब्स और रूमर्स : प्रेग्नेंसी और सुसाइड करने की उड़ती अफवाहों पर दिया इलियाना डिक्रूज ने अपना रिएक्शन, बोलीं- बहुत दुख होता है

बॉलीवुड सेलेब्स अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ से जुड़ी खबरों से ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। खबरों के साथ-साथ सेलेब्स से जुड़ी अफवाहें भी कई बार चर्चा का विषय बन जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इलियाना डिक्रूज के साथ जिनकी प्रेग्नेंसी और सुसाइड की खबरें कुछ महीनों पहले जारी हुई थीं। अब एक्ट्रेस ने इस तरह की फेक न्यूज और अफवाहों पर अपना रिएक्शन देते हुए इन्हें बेतुका बताया है। बता दें कि साउथ इंडस्ट्री में पहचान बनाने के बाद इलियाना ने बॉलीवुड में बर्फी, मैं तेरा हीरो और रुस्तम जैसी फिल्में दी हैं।

2018 में उड़ी थी प्रेग्नेंसी की अफवाह

हाल ही में बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में इलियाना ने फेक न्यूज और अफवाहों पर कहा, मुझसे जुड़ी कुछ अफवाहें हैं। एक ऐसी खबर थी जिसमें मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने अबॉर्शन करवाया था। ये काफी दुखी करने वाला था। सच कहूं तो कुछ लोग ऐसी ही चीजें लिखते हैं। ये बहुत बेतुका है। बता दें कि साल 2018 में खबरें उड़ी थीं कि इलियाना डिक्रूज प्रेग्नेंट हैं। हालांकि एक्ट्रेस ने इन सभी अफवाहों को साफ करते हुए उसी समय सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसके साथ उन्होंने लिखा था, नॉट प्रेग्नेंट।

महामारी में मददगार सितारे

अब फरहान अख्तर ने कोरोना पीड़ितों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ

एक्सल प्रोडक्शन के जरिए कई एनजीओ को दिया डोनेशन

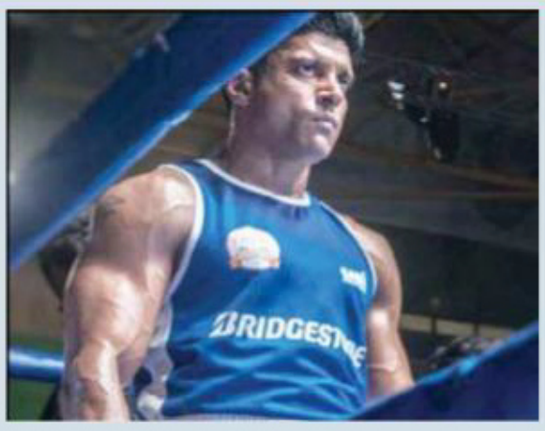

देश में कोविड 19 की दूसरी लहर आते ही लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लगातार पीड़ितों को ऑक्सीजन, दवाइयों और जरूरी सामान की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस मुश्किल समय में अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स अपना योगदान दे रहे हैं जिनमें अब फरहान अख्तर का नाम भी जुड़ चुका है। फरहान ने हाल ही में अपने प्रोडक्शन एक्सल मूवीज के जरिए कई एनजीओ को डोनेशन दिया है जो ग्राउंड लेवल पर लोगों को ऑक्सीजन और खाना मुहैया करवा रहे हैं। इन एनजीओ की जानकारी भी एक्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। डोनेशन के बाद फरहान ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लिखा, उन ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट शेयर कर रहा हूं जिन्हें अब तक एक्सल मूवीज ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए डोनेशन दिया है। ऑक्सीजन से लेकर एंबुलेंस और खाने तक, ये लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपको भी अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। हर रुपया महत्व रखता है। जय हिंद। पोस्ट में फरहान ने एक्सल मूवीज के पार्टनर रितेश सिधवानी को भी मेंशन किया है।

सोशल मीडिया पर दे रहे हैं कोरोना से जुड़ी सही जानकारी

फरहान अख्तर डोनेशन के अलावा भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों की मदद कर रहे हैं। एक्टर लगातार अपने ट्विटर पर ऑक्सीजन, एंबुलेंस और दवाइयों की सही जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही एक्टर ने फैंस और जनता से ज्यादा से ज्यादा डोनेट करने की अपील भी की है। फरहान अख्तर जल्द ही राकेश ओमप्रकाश के निर्देशन में बनी फिल्म तूफान में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में फरहान एक मुक्केबाज की भूमिका में हैं। फिल्म को पहले सिनेमाघरों के लिए तैयार किया गया था हालांकि महामारी को देखते हुए अब इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा।

कोविड अपडेट:रणधीर कपूर बोले-

ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी जल्दी घर आऊंगा, स्वरा भास्कर की मां हुईं रिकवर लेकिन जैस्मीन भसीन को हुई परेशानी

हाल ही में रणधीर कपूर को कोरोना संक्रमण के कारण हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। अब उन्होंने अपनी सेहत के बारे में अपडेट देते हुए कहा है कि वे पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें घर वापस जाने की परमीशन मिल जाएगी। रणधीर दो दिन तक आईसीयू में थे। हालांकि उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी और न ही उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत हुई, उन्हें केवल बुखार था।

स्वरा की मां इरा ने कोरोना को हराया

दूसरी ओर स्वरा भास्कर की मां इरा कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गई हैं। स्वरा ने सोशल मीडिया पर मां की एक फोटो के साथ यह जानकारी शेयर की। स्वरा ने लिखा- यह बहुत बुरा समय है, लेकिन इस बीच कुछ अच्छी खबर भी शेयर करती हूं। मां और बिकेश, इन दोनों को कोरोना संक्रमण हुआ था अब वे दोनों ही निगेटिव हो गए हैं। 14 दिन बाद, जब वे बुखार और ऑक्सीजन के उतार-चढ़ाव से जूझ रहे थे। बहुत ही अच्छा और लकी महसूस कर रही हूं। आप सभी की शुभकामनाओं का शुक्रिया। जो लोग पीड़ित हैं उनके परिवारों के लिए दुआ करती हूं।

जैस्मीन को जूझना पड़ा बेड के लिए

बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट रहीं जैस्मीन भसीन की मां को कोरोना संक्रमण के बाद हॉस्पिटल में एक बेड के लिए परेशान होना पड़ा। जैस्मीन ने सोशल मीडिया पर लिखा- दुखद और दिल तोड़ने वाला। हर दिन मौतें, लोग सड़कों पर बेड्स और ऑक्सीजन खोज रहे हैं। दो दिन पहले मेरी मां भी इसी हाल में थी। एक बेड को खोजना मुश्किल हो गया था। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मेरे बुजुर्ग पिता चक्कर लगा रहे थे। दूसरे भी इन हालातों से गुजर रहे हैं।

कोरोना का असर-

18 दिन से अटकी पड़ी है रणवीर सिंह स्टारर 'सर्कस' की सिर्फ एक दिन की शूटिंग,

ऊटी में नहीं मिली शूट की इजाजत तो महबूब स्टूडियो में बनाया सेट

कोविड की दूसरी लहर ने मेगाबजट फिल्मों की शूटिंग पर भी ब्रेक लगा दिया है। मजबूरन मेकर्स को शूटिंग करने के नए तरीके निकालने पड़ रहे हैं। लेकिन, कुछ फिल्मों के लिए कोई तरीका काम नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर रणवीर सिंह और जैकलीन फर्नांडीज स्टारर फिल्म 卐सर्कस को ही ले लीजिए। वैसे तो यह फिल्म तकरीबन पूरी शूट हो चुकी है, पर इसकी सिर्फ एक दिन की शूटिंग बीते 18 दिनों से अटकी पड़ी है।

ज्यादा क्रू मेंबर्स होने के चलते नहीं मिली शूटिंग की इजाजत

फिल्म से जुड़ सूत्रों ने बताया, 卐पूरी टीम 12 अप्रैल को शूटिंग के लिए ऊटी जाने वाली थी। वहां डबल रोल में रणवीर सिंह के जैकलीन और पूजा हेगड़ के साथ रोमांटिक सीन फिल्माए जाने थे। इन सभी सीन के बैकग्राउंड में 50 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्टों को रखा जाना था। पूरी यूनिट को संभालने के लिए 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स की टीम भी जाती, मगर ऊटी प्रशासन ने वहां इतनी तादाद में शूटिंग करने की इजाजत नहीं दी। ऐसे में मेकर्स ने महबूब स्टूडियो के इंडोर में ही ऊटी का सेट बनाना शुरू कर दिया, मगर कोविड प्रोटोकॉल के चलते अब महाराष्ट्र में भी शूटिंग बंद होने के चलते वह काम भी अटक गया है।

वीएफएक्स के जरिए दिखाए जाएंगे सर्कस के जानवर

फिल्म से जुड़े ऑफिशियल्स ने बताया, 卐फिल्म का टाइटल जरूर 'सर्कस' है, मगर इसमें बंद पिंजरों में ही असली जानवरों के साथ शूटिंग नहीं की जा रही। फिल्म में 80 फीसदी से ज्यादा वीएफएक्स वर्क होगा। मेकर्स ने स्टूडियो में जानवरों के स्टेच्यू लगाकर सीन शूट कर लिए हैं। अब वीएफएक्स की मदद से उन्हें जीवंत किया जाएगा। जैसा 'टोटल धमाल' में किया गया था। फिल्म के लिए रणवीर ने उड़ती गाड़ियों के साथ भी कुछ स्टंट सीन शूट किए हैं। मगर उन्हें भी जुगाड़ लगाकर स्टूडियो के अंदर ही शूट किया गया है। 'सर्कस' रोहित शेट्टी की पहली ऐसी फिल्म होगी, जिसकी ज्यादा से ज्यादा शूटिंग स्टूडियोज के अंदर ही की गई है।

बड़े बजट की ये फिल्में भी अटकीं

- 'सर्कस' के अलावा और भी कई बड़े बजट की फिल्में हैं, जिनकी शूटिंग अटकी हुई है। जानिए...
- आलिया भट्ट स्टारर ' गंगूबाई' का भी महज एक दिन का काम बाकी है।
- अजय देवगन की 'मेडे' और 卐मैदान।
- शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर 'पठान'।
- सलमान-कटरीना की 'टाइगर 3'।
- वरुण धवन की 'जुग जुग जियो'।

कोरोना से रिकवर होते ही काम पर लौटे आमिर खान, लद्दाख में शूट हो रहा है लाल सिंह चड्ढा फिल्म का फाइनल शेड्यूल

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान कुछ दिनों पहले ही कोविड 19 की चपेट में आ गए थे जिससे अब एक्टर रिकवर हो चुके हैं। रिकवर होने के तुरंत बाद ही एक्टर ने बिना ब्रेक लिए दोबारा काम पर वापसी कर ली है। एक्टर अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की बची हुई शूटिंग लद्दाख में कर रहे हैं जहां से लगातार तस्वीरें और वीडियोज सामने आ रही हैं। हाल ही में आई ई-टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में लाल सिंह चड्ढा फिल्म का अहम हिस्सा शूट किया जा रहा है। यहां एक्टर 45 दिनों तक शूट करने वाले हैं। इस फिल्म में पहले विजय सेतुपति भी आमिर खान के साथ नजर आने वाले थे हालांकि अब उन्हें नाग चैतन्य ने रिप्लेस कर दिया है। अब जल्द ही नाग चैतन्य भी शूटिंग खत्म करने के लिए लद्दाख पहंचने वाले हैं।

कोरोना महामारी के चलते बदली गई लोकेशन

आमिर खान की फिल्म में कारगिल वॉर का सीन दिखाया जाना है जिसकी शूटिंग पहले विदेश में की जानी थी। आमिर खान लोकेशन देखने भी गए थे हालांकि लॉकडाउन और महामारी के चलते विदेश में शूटिंग किया जाना मुमकिन नहीं हो सका। अब फिल्म में युद्ध का सीन दिखाने के लिए लद्दाख में ही कारगिल का सेट तैयार किया गया है।

फॉरेस्ट गंप की हिंदी रीमेक है लाल सिंह चड्ढा

आमिर खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप की हिंदी रीमेक होने वाली है। ऑरिजिनल फिल्म में टॉम हैंक्स ने लीड रोल निभाया था। इस फिल्म को 2020 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज किया जाने वाला था हालांकि लॉकडाउन के चलते शूटिंग पूरी नहीं हो सकी। फिलहाल मेकर्स इसे इस साल के आखिर तक रिलीज करने की तैयारी में है।

बड़े दिल वाला

विजय देवरकोंडा ने अस्पताल में भर्ती फैन की आखिरी ख्वाहिश की पूरी, नम आंखों के साथ कहा- तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं

जल्द ही फिल्म लीगर से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री करने वाले विजय देवरकोंडा ने हाल ही में अपने एक फैन की आखिरी ख्वाहिश पूरी की है। उनका फैन हेमंत कोरोना पॉजिटिव था और अस्पताल में भर्ती था जब उसने विजय से बात करने की इच्छा जताई थी। जब विजय को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी टीम भेजकर हेमंत से वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत की। अपने फैन से बात करते हुए एक्टर अपने आंसू नहीं रोक सके। इस बेहद खास फैन मूमेंट को एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।विजय ने अपने फैन के साथ वीडियो कॉलिंग करते हुए एक स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। इसके साथ एक्टर ने लिखा, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूं हेमंत.. मुझे बहुत खुशी है कि अपनी बात हुई और मुझे तुम्हारी मीठी सी मुस्कान देखने का मौका मिला। तुम्हारा प्यार महसूस हुआ और तुम्हें थोड़ा प्यार दिया। आखों में आंसुओं के साथ मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं। सबका शुक्रिया जिसने मुझे इस छोटे स्वीट से लडके से कनेक्ट करने में मेरी मदद की।

ये थे विजय के लिए हेमंत के आखिरी शब्द

- इस वीडियो कॉलिंग के बाद हेमंत ने विजय से उनकी राउडी ब्रांड की एक टी-शर्ट की गुजारिश की थी। साथ ही हेमंत ने कहा, अन्ना, आपसे बात करने के बाद बहुत आराम मिला है। बहुत अच्छा होता अगर मुझे कोविड ना होता।
- विजय देवरकोंडा जल्द ही पुरी जगन्नाथ के निर्देशन में बन रही फिल्म लीगर से बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे भी लीड रोल में नजर आने वाली हैं जिसे 9 सितंबर 2021 में रिलीज करने के लिए शेड्यूल किया गया है। फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है।

आईपीएल निलंबित होने के बाद घर लौटे विराट

मुम्बई, (एजेंसी)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 14वां सत्र निलंबित होने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (सीएसके) के कप्तान विराट कोहली भी घर लौट गये हैं। आईपीएल का बचा हुआ सीजन अब कब, कहां और कैसे खेला जाएगा, इसको लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में विराट के अलावा अन्य खिलाड़ी भी अपने-अपने घर की तरफ लौटने लगे हैं।

मुंबई लौटने के बाद विराट अब अपनी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में देश सेवा करेंगे। वहीं इससे पहले अभिनेत्री अनुष्का ने एक मई को अपना जन्मदिन भी नहीं मनाया था। अनुष्का ने प्रशंसकों से कहा था कि इस कठिन घड़ी में सभी एकजुट होकर देश का समर्थन करें। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि विराट और वो देश के लिए अपना काम कर रहे हैं और वह जल्द ही इसके बारे में जानकारी देंगे। वहीं इससे पहले आईपीएल के स्थगित होने का सभी टीमों ने स्वागत किया था हालांकि यात्रा प्रतिबंधों के कारण विदेशी खिलाड़ी सुरक्षित स्वदेश लौटने के लिए बीसीसीआई के कदम का इंतजार कर रहे हैं। आईपीएल के चेयरमैन बृजेश पटेल ने अपने एक बयान में कहा, लीग की संचालन परिषद और बीसीसीआई की आपात बैठक में सर्वसम्मति से आईपीएल 2021 सत्र तुरंत प्रभाव से स्थगित करने का फैसला लिया गया था। उन्होंने कहा, बीसीसीआई खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और अन्य प्रतियोगियों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहता। यह फैसला सभी संबंधित पक्षों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और भलाई को ध्यान में रखकर लिया गया, साथ ही कहा कि विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षित वापसी का भी रास्ता तलाश जाएगा।

कोरोना के कारण प्रभावित हुई हैं आईपीएल सहित सभी स्पोर्ट्स लीग

मुम्बई, (एजेंसी)। कोरोना संक्रमण के कारण खेल भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जैव सुरक्षा घेरे के बाद भी कुछ खिलाड़ियों में कोरोना संक्रमण के मामले पाये जाने के बाद आईपीएल 2021 भी अनिश्चितकाल के लिए निलंबित हो गया है जबकि इसके 29 मुकाबले ठीक प्रकार से हो गये थे। आईपीएल के निलंबित होने के कारण इसके राजस्व में भी कमी होगी और लीग को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कोरोना के कारण आईपीएल का पिछला सत्र यूएई में बिना प्रशंसकों के कराया गया था। इस कारण आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 3.6 फीसदी गिर गई थी। डफ एंड फेल्प्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल आईपीएल की ब्रांड वैल्यू लगभग 46 हजार करोड़ रुपये थी। वहीं एक साल पहले यह वैल्यू लगभग 47 हजार 500 करोड़ रुपये थी।

वहीं क्रिकेट के अलावा अन्य सभी खेलों की लीग को इसी प्रकार नुकसान उठाना पड़ रहा है। साल 2021 फुटबॉल लीग के आंकड़े को देखें तो स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के राजस्व में करीब 1100 करोड़ रुपये की कमी आई है। इस शीर्ष 20 फुटबॉल क्लब को लगभग 73 हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला जो पिछले साल के मुकाबले 9 हजार करोड़ रुपये कम था। पिछले सत्र में क्लबों का रेवेन्यू लगभग 82 हजार करोड़ रुपये रहा था। वहीं इसी प्रकार अमेरिका की बेसबॉल लीग को भी कई हजार करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा है। कोरोना के कारण लगी पाबंदियों को देखते हुए प्रशंसकों के स्टेडियम में आने पर भी रोक लगी हुई है। इस कारण क्लबों को टिकट से मिलने वाला राजस्व भी कम हुआ है। इसे कम करने के लिए क्लब नई यूरोपियन लीग शुरू करने जा रहे थे पर विरोध के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा है। वहीं कई लीग तो अपने मुकाबले शुरू भी नहीं कर पा रही हैं।

चीन में महिलाओं की बटरफ्लाई स्पर्धा में भाग लेती हुई जियांग्सू की झांग यूफेई।

स्पेनिश इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पायेंगे भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत के शीर्ष पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत और सुकांत कदम कोविड-19 महामारी को देखते हुए बने कड़े पृथकवास नियमों के कारण 11 से 16 मई तक होने वाले स्पेनिश इंटरनेशनल टूनार्मेंट में भाग नहीं ले पायेंगे। इसका कारण यह है कि स्पेन ने भारत से आने वाले यात्रियों के लिए 10 दिन का अनिवार्य पृथकवास नियम लागू किया है जिसके कारण इन खिलाड़ियों के लिए टूनार्मेंट में भाग लेना संभव नहीं है।

वहीं भगत ने कहा, दुबई पैरा बैडमिंटन टूनार्मेंट में शानदार प्रदर्शन के बाद मैं स्पेनिश इंटरनेशनल में हिस्सा लेने को लेकर उत्सुक था क्योंकि यह पैरालंपिक से पहले आखिरी टूनार्मेंट था। साथ ही कहा, मैं इसका इस्तेमाल टोक्यो में पैरालंपिक की तैयारी के अवसर के रूप में करना चाहता था हालांकि मैं समझ सकता हूं कि ये मुश्किल समय है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे कोविड नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें।

भगत और सुकांत पिछले महीने दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम में शामिल थे। इस टीम ने 4 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य पदक जीते थे। सुकांत ने कहा, हां, इससे हमारी तैयारियां थोड़ी प्रभावित होंगी क्योंकि हम पैरालंपिक से पहले अधिक प्रतिस्पर्धी टूनार्मेंट खेलना चाहते थे। मैं इस टूनार्मेंट को लेकर विशेष रूप से उत्साहित था क्योंकि यहां स्वर्ण पदक जीतकर मैं रेस टू तोक्यो रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच सकता था।

वान ने आईपीएल स्थगित किये जाने को सही बताया

सिडनी, (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) लीग को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के फैसले को सही बताया है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान वॉन ने ट्वीट किया, आईपीएल को स्थगित करने का फैसला बहुत समझदारी भरा लगा। उन्होंने साथ ही लिखा, जब बायो बबल के अंदर भी संक्रमण के मामले आने लगे तो उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। साथ ही उम्मीद जतायी कि भारत में सभी लोग सुरक्षित होंगे और विदेशी खिलाड़ी अपने परिवार तक पहुंच सकेंगे।

वहीं आईपीएल रद्द होने को लेकर बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा था कि वर्तमान समय में कोविड-19 के हालात पर नजर रखते हुए बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने लीग को स्थगित करने का फैसला किया। हम खिलाड़ियों, इसमें शामिल लोगों, कर्मचारियों, मैदानों, मैच अधिकारियों, हर एक व्यक्ति जो इसमें शामिल है, की सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहते थे। वहीं विदेशी खिलाड़ियों को अपने देश सुरक्षित भेजने पर आईपीएल चेयरमैन बृजेश पटेल ने कहा, हमें उन्हें स्वदेश भेजने की जरूरत है और हम ऐसा करने का तरीका तलाश लेंगे।

इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ियों और क्लबों ने किया सोशल मीडिया का बहिष्कार

लंदन, (एजेंसी)। इंग्लैंड के प्रमुख फुटबॉल क्लबों, लीग प्रबंधकों और खिलाडिों ने साइबर बुलिंग (ऑनलाइन अभ्रदता) के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करने के लिए चार दिनों तक सोशल मीडिया साइट (फेसबुक, ट्विटर इंस्टाग्राम) आदि का बहिष्कर किया। इसी मुहिम के तहत मैनचैस्टर युनाइटेड ने प्रीमियर लीग में मिली जीत पर भी सोशल मीडिया पर कोई जश्न नहीं मनाया। इस मुहिम में इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन, प्रीमियर लीग, वुमन सुपर लीग, वुमन चैम्पियनशिप से जुड़े सभी सदस्यों ने भी भाग लिया।

वहीं मैनचैस्टर युनाइटेड क्लब ने बुलिंग पर विरोध जताने के लिए सभी प्रशंसकों को ब्लॉक कर दिया है। क्लब ने पाया कि सितंबर 2019 से लेकर फरवरी 2021 तक उनके खिलाड़ियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर 3300 से ज्यादा शिकायतें आई थीं। वहीं एक अन्य क्लब चेलिसी ने भी ऐसे ही मामले आने पर 10 दिन का प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इंग्लिश फुटबॉल लीग और प्रीमियर लीग ने इसके साथ ही अपने सभी क्लब सदस्यों के साथ मिलकर सोशल मीडिया की तीनों बड़ी कंपनियां फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से अपील की है कि वह अपने प्लेटफार्म पर ऑनलाइन अभद्र व्यवहार को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाएं।

आईसीसी के महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार की दौड़ में नेपाल के कुशाल शामिल

दुबई, (एजेंसी)। आईसीसी के महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नेपाल के बल्लेबाज कुशाल भुर्तेल भी दौड़ में शामिल हैं। पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम और फखर जमां के साथ ही नेपाल के कुशाल को अप्रैल के लिए आईसीसी के महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है।

बाबर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय मैच में 82 गेंदों पर 94 रन की शानदार पारी खेली थी। इस पारी के बल पर वह 13 अंक हासिल करके करियर की सर्वश्रेष्ठ 865 रेटिंग पर पहुंच गए थे। वहीं अप्रैल महीने में ही फखर जमां ने भी शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो शतक लगाये थे। दूसरे मैच में उन्होंने 193 रन की पारी खेली थी। आजम और फखर को इस अवॉर्ड की दौड़ में टक्कर देने वाले नेपाल के कुशाल ने नीदरलैंड्स और मलेशिया के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाये थे। इससे उनकी टीम ने यह सीरीज भी जीती थी। कुशाल ने पांच अर्धशतकों के साथ ही कुल 278 रन बनाए थे।

कोरोना पीड़ितों के लिए गुप्त दान करेगा यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत में कोरोना संक्रमण से हुई विकराल स्थिति को देखते हुए पीड़ितों की सहायता के लिए दुनिया भर में कई लोग और संगठन सामने आये हैं। इसी के तहत ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जैसन बेहरेनडोर्फ ने भी कोरोना पीड़ितों के लिए गुप्त दान देने की बात कही है। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की ओर से खेल रहे तेज गेंदबाज जैसन बेहरेनडोर्फ ने कहा है कि वह यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया की भारत में कोरोना संकट में सहायता की अपील को देखते हुए गुप्त रुप से दान देंगे। इस गेंदबाज ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर दूसरों से भी दान देने का अनुरोध किया है। भारत में पिछले कुछ दिन से कोरोना महामारी से रोज तीन हजार से अधिक लोगों की मौत हो रही हैं। बेहरेनडोर्फ ने लिखा, मैं सहायता के लिए कुछ करना चाहता था और इसी लिए मैंने भारत में कोरोना संकट से निपटने के लिए यूनिसेफ के प्रोजेक्ट में दान दिया है। इसके साथ ही मैं दूसरों से भी अपील करता हूं कि वे अधिक से अधिक दान करें जिससे पीड़ितों की कुछ हद तक सहायता हो सके।

उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि यह रकम छोटी है। इसकी तुलना उस प्यार और दोस्ती से नहीं हो सकती जो भारत में हमें मिली है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ तो फर्क पड़ेगा। इससे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) के अलावा पैट कमिंस सहित कई अन्य ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने कोरोना पीड़ितों के लिए सहायात देने की घोषणा की थी।

आईपीएल में फर्जी तरीके से प्रवेश करने वाले दो लोगों को पुलिस हिरासत में भेजा गया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आईपीएल का 14वें सत्र हालांकि निलंबित हो गया है पर इसमें 2 मई को राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गये मैच में फर्जी तरीके से प्रवेश का प्रयास कर रहे दो लोगों को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। आईपीसी और महामारी रोग अधिनियम की धाराओं के तहत दोनों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने हैदराबाद को 55 रनों से हराया था। ऋद्धिमान साहा और अमित मिश्रा की कोविड रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल के इस सत्र को स्थगित कर दिया था।

वहीं बीसीसीआई की तरफ से यह कहा गया है कि टूनार्मेंट को सिर्फ स्थगित किया गया है। अब बोर्ड टी20 लीग के लिए नए विंडो की तलाश कर रहा है हालांकि व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए यह आसान नहीं होगा। आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने कहा कि टी20 लीग के बचे हुए 31 मुकाबले विश्व कप से पहले या बाद में कराए जा सकते हैं। इसके लिए हम विंडो की तलाश कर रहे हैं। गौरतलब है कि जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में कोविड-19 मामलों के कारण आईपीएल को स्थगित करने से बीसीसीआई को लगभग 2500 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है।

टोक्यो ओलंपिक में अवसरों का लाभ उठाना होगा : ललित

बेंगलुरू। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के फारवर्ड ललित उपाध्याय ने कहा है कि भारतीय खिलाड़ियों को आगामी टोक्यो ओलंपिक से पहले अवसरों को गोल में बदलने में और पारंगत होना पड़ेगा। ललित के अनुसार अर्जेंटीना के हाल के दौरे में भारतीय टीम ने चार अभ्यास मैचों में 12 गोल के साथ ही ओलंपिक चैंपियन के खिलाफ दो एफआईएच प्रो लीग मैचों में पांच गोल किये थे पर ओलंपिक को देखते हुए इसमें अब भी भी सुधार करना होगा। इसका कारण है कि भारतीय टीम ने जो 12 गोल किये थे उनमें से नौ गोल पेनल्टी कार्नर पर किये गए। ऐसे में टीम को मैदानी गोल करने का और अभ्यास करना होगा। ललित ने कहा कि अर्जेंटीना के खिलाफ मैच बड़े स्कोर वाले थे और बेहतर रक्षापंक्ति वाली अर्जेंटीना जैसी टीम के खिलाफ मैदानी गोल करना आसान नहीं था पर पिछले कुछ महीनों में हमने अवसरों को गोल में बदलने और पेनल्टी कार्नर हासिल करने पर काफी अभ्यास किया है। हमने इस पर भी काम किया है कि हमें 25 मीटर के सर्किल में कैसे काम करना चाहिए। टीम को सर्किल के अंदर रहते हुए अवसरों का लाभ उठाने आक्रामक रुख अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि हम अभी शिविर में इसी बात पर ध्यान दे रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद भी टीम टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीतने में सक्षम है। सभी खिलाड़ियों का मानना है कि यह हमारे पास पदक जीतने का सबसे अच्छा अवसर है।

चीन के हीनन प्रांत में विश्व टेबल टेनिस मुकाबले में भाग लेते हुए मे लयोंग।

टेलर का इंग्लैंड दौरे पर जाना संदिग्ध

वेलिंगटन, (एजेंसी)। न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज रॉस टेलर का इंग्लैंड दौरे पर जाना संदिग्ध नजर आ रहा है। टेलर यहां अभ्यास के दौरान चोटिल हो गये थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा है कि उनकी पिंडली में खिंचाव आया है।

न्यूजीलैंड क्रिकेट को हालांकि उम्मीद है कि अगले सप्ताह इंग्लैंड के लिए रवाना होने और टेस्ट टीम से जुड़ने से पहले टेलर ठीक हो जाएंगे। वहीं न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टेड ने माना है कि टेलर को लगी चोट थोड़ी चिंताजनक है।

उन्होंने कहा कि टेलर हमारे सबसे अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं। उन्हें चोट लगने से समस्या और भी बढ़ जाती है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी सब कुछ सही हो जाये। हमारे पास अभी समय है, हालांकि हमें अपनी मेडिकल टीम की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। इससे पहले बंगलादेश के खिलाफ दो मैचों की एकदिवसीय सीरीज में भी टेलर चोट के कारण खेल नहीं पाये थे। न्यूजीलैंड की टीम मई के मध्य में इंग्लैंड दौरे पर जाएगी जहां उसे मेजबान टीम के खिलाफ दो जून से टेस्ट सीरीज खेलनी है और इसके बाद वह साउथम्पटन में भारत के खिलाफ आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में खेलेगी। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए अपनी 20 सदस्यीय टीम भी घोषित कर दी है।

बटलर ने यशस्वी को दिया विशेष उपहार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कोरोना महामारी के कारण जहां आईपीएल लीग निलंबित कर दी गयी है। वहीं राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जोस बटलर ने अपने जोड़ीदार यशस्वी जायसवाल को एक विशेष उपहार दिया है। रॉयल्स ने एक तस्वीर साझा करके कहा है कि बटलर ने अपने शुरूआती जोड़ीदार यशस्वी को 64 गेंदों पर 124 रन बनाने के बाद एक खास उपहार दिया था। बटलर ने सनराइजर्स के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 124 रन की पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 8 छक्के लगाए थे। मैच के बाद बटलर ने अपना ऑटोग्राफ वाला बल्ला यशस्वी को उपहार में दिया।

बटलर के इस उपहार से जायसवाल काफी उत्साहित नजर आये। रॉयल्स ने इस उपहार की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की हैं। बटलर ने इसके साथ ही जायसवाल के लिए एक विशेष संदेश भी लिखा है। इस बल्ले पर उन्होंने लिखा था कि अपनी प्रतिभा का लाभ उठायें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।